CNews सिटी चीफ

वर्ष-14, अंक-322
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

आज का विचार
धैर्य का छोटा हिस्सा भी एक टन उपदेश से बेहतर है। -महात्मा गांधी

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

सिटी चीफ

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार
पेज-04
इंदौर, शनिवार 24 फरवरी 2024

सीएम हिमंता सरमा ने कही ये बात

असम सरकार का बड़ा फैसला, खत्म किया मुस्लिम विवाह एवं तलाक कानून

गुवाहाटी। असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर रोक के लिए मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून, 1935 खत्म कर दिया है। शुक्रवार देर रात हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि '23 फरवरी को असम कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए वर्षों पुराने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया गया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए हैं, तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। यह असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में अहम कदम है।'

मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार को मुआवजा देगी असम सरकार: असम सरकार ने बताया कि मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून खत्म होने के बाद मुस्लिमों की शादी का पंजीकरण भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार कर सकेंगे, जो कि पहले 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार करते थे। सरकार ने एलान किया है कि मुस्लिम विवाह का पंजीकरण करने वाले रजिस्ट्रार्स को हटाया जाएगा और उन्हें एकमुश्त दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। असम सरकार ने कानून हटाने के पीछे तर्क दिया है कि ये कानून अंग्रेजी शासनकाल के दौर के हैं। सरकार का कहना है कि मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून के तहत शादी और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। साथ ही शादी का पंजीकरण करने की व्यवस्था पूरी तरह से अनौपचारिक थी, जिससे नियमों की अनदेखी हो रही थी और बाल विवाह की भी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। कानून के तहत राज्य सरकार मुस्लिमों को शादी और तलाक का पंजीकरण करने का लाइसेंस देती थी, लेकिन अब कानून हटने के बाद कोई भी व्यक्ति शादी और तलाक का पंजीकरण नहीं कर सकेगा और यह औपचारिक रूप से हो सकेगा। राज्य सरकार के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने मीडिया चैनल से बात करते हुए ये भी दावा किया कि इस कानून का खत्म होना राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में अहम कदम है।

बांग्लादेश से भारत में घुसे

पुलिस की नाक के नीचे 'टेंट सिटी' बसाकर बनाया काला साम्राज्य

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल से पड़ोसी देश बांग्लादेश की सीमा लगती है. दोनों देश के बीच सड़क संपर्क के जरिये लोगों का आना-जाना होता है. साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार भी होता है. भारत-बांग्लादेश की सीमा घने जंगल से भी घिरा हुआ है. अवैध धंधा करने वाले इसी का फायदा उठाकर भारत में घुस आते हैं. अवैध तरीके से भारत आने वाले बांग्लादेशी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चिंता का सबब बन जाते हैं. अब जरा सोचिए अवैध तरीके से भारत आने वाले बांग्लादेशी यदि टेंट सिटी बसा ले तो फिर क्या हो? राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक ऐसे ही रैकेट का भंडाफोड़ किया है. जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने मानव तस्करी के एक मामले में कर्नाटक से दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि कर्नाटक के आंतरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ की मदद से बांग्लादेशी नागरिकों (मोहम्मद साज्जिद हलदर और इदरिस) का पता

लगाया गया. इन दोनों को बृहस्पतिवार को पकड़ा गया था. ये काफी दिनों से फरार चल रहे थे. उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. जांच एजेंसी के प्रवक्ता के अनुसार, एनआईए ने जांच के दौरान पाया कि हलदर और इदरिस भारत-बांग्लादेश सीमा पर बेनापोल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे. NIA ने देशव्यापी छापे के बाद नवंबर 2023 में (मानव तस्करी के) इस मामले का भंडाफोड़ किया था. अधिकारी ने बताया कि हलदर ने बेंगलुरु में रामामूर्ति नगर में 'कबाड़ संग्रहण एवं पृथक्करण' इकाई लगायी थी और उसमें अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को काम पर रखा था. उन्होंने बताया कि जांच से यह भी पता चला कि इदरिस ने भी बेंगलुरु के आनंदपुरा में कबाड़ संग्रहण एवं पृथक्करण इकाई लगायी थी जहां उसने लीज पर जमीन ली थी एवं वहां 20 से अधिक बांग्लादेशी परिवारों के लिए टेंट लगाये थे. संदेह है कि इन परिवारों को उसने ही तस्करी के जरिए भारत में दाखिल कराया था. प्रवक्ता ने कहा कि इन विवरणों की पुष्टि के लिए जांच जारी है.

स्कूल में भूत है! 'बाल खोलकर चिल्लाने लगती हैं छात्राएं', शिक्षक भी परेशान...

__शहडोल।__ शहडोल जिले के बुढ़ार विकासखंड में एक स्कूल इन दिनों चर्चाओं में है। स्कूल आते ही बच्चे स्कूल प्रांगण में रही प्रार्थना के दौरान एक-दूसरे को देख झूमने लगते हैं। यहां पढ़ने वाली छात्राएं अजीब-अजीब हरकतें कर रही हैं और अचानक रोने लगती हैं। छात्राओं की हरकतें देखकर स्कूल में झाड़ फूंक कराया जा रहा है। झाड़ फूंक के कुछ देर बाद बच्चे अजीब हरकतें करना बंद कर देते हैं। छात्राओं के इस तरह के व्यवहार से पालकों और ग्रामीणों में स्कूल में भूत-प्रेत का साया होने का अंदेशा होने लगा है। मामला शहडोल जिले के बुढ़ार विकासखंड के शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय छोटकी टोला का है। जहां स्कूल आते ही छात्राएं किसी समस्या के

चलते अजीब हरकत कर रही हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे इन पर भूत प्रेत का कोई साया चढ़ गया है। अचानक हुई इस घटना से स्कूल के टीचर भी परेशान हैं। मामले को लेकर आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर आनंद राय सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। सभी बच्चों की विभिन्न प्रकार की जांच की जा रही है। डॉक्टर और मनोचिकित्सा बच्चों को काउंसलिंग कर रहे हैं। पिछली बार भी जिले में इस तरह के मामले सामने आए थे। लेकिन, काउंसलिंग करने के कुछ दिनों के अंदर यह दिक्कत दूर हो गई थी।

दूसरे संयंत्र की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे लारा थर्मल प्लांट

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एनटीपीसी के 1,600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये राष्ट्र को समर्पित करेंगे और दूसरे चरण के तहत 1,600 मेगावाट के अन्य संयंत्र की आधारशिला रखेंगे।

बिजली मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि स्टेशन का पहला चरण लगभग 15,800 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है, जबकि परियोजना के दूसरे चरण में 15,530 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति एनटीपीसी के तलाईपल्ली कोयला ब्लॉक से मैरी-गो-राउंड (एमजीआर) प्रणाली के माध्यम से की जाएगी, जिससे देश को कम लागत वाली बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सभी इकाइयों में कोयला की खपत कम होगी और कार्बन-डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की तीन परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन- प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की 600 करोड़ रुपये लागत वाली तीन फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का टेली कान्फ्रेंसिंग के जरिये उद्घाटन करेंगे। एसईसीएल कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। पहली परियोजना दीपका ओपन कास्ट प्रोजेक्ट (ओसीपी) है जिसका निर्माण 211 करोड़ से अधिक की लागत से किया गया है। दूसरी परियोजना 173 करोड़ लागत वाली छाल ओसीपी है। तीसरी परियोजना 216 करोड़ रुपये की लागत वाली बरौद ओसीपी कोयला हैंडलिंग प्लांट है।

कल यूपी-गुजरात समेत 5 एम्स का करेंगे उद्घाटन- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राजकोट में गुजरात के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) समेत पांच एम्स का उद्घाटन करेंगे। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मंगलागिरि (आंध्र प्रदेश), बठिंडा (पंजाब), रायबरेली (उत्तर प्रदेश) और कल्याणी (प. बंगाल) में स्थित चार अन्य नवनिर्मित एम्स का भी टेली कान्फ्रेंसिंग के जरिये उद्घाटन करेंगे। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने शुक्रवार को कहा कि राजकोट शहर के बाहरी इलाके में पारा पिपलिया गांव के पास सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल का बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) पहले से ही चालू है, पीएम मोदी आंतरिक रोगी विभाग (आईपीडी) का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने दिसंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राजकोट एम्स की आधारशिला रखी थी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़े अनाज भंडारण की पायलट परियोजना का उद्घाटन करेंगे। परियोजना 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में संचालित किया जा रहा है। पीएम मोदी इस दौरान, सहकारी क्षेत्र की और योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

कांग्रेस-AAP में डील डन, दिल्ली-हरियाणा समेत पांच राज्यों में गठबंधन का एलान आज,थोड़ी देर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस

लोकसभा चुनाव से पहले INDI गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पांच राज्यों के लिए गठबंधन का एलान हो सकता है। जानकारी के अनुसार, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और गुजरात में एकसाथ चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस और AAP घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। इसे लेकर आप औपचारिक तौर पर घोषणा हो सकती है। बताया जा रहा है कि हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट आप के खाते में जा सकती है वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि महत्वपूर्ण बात यह है कि औपचारिक तौर से उत्तर प्रदेश में गठबंधन की घोषणा की गई है। इसे अंतिम रूप देने में समय लगा है। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी गठबंधन का औपचारिक तौर से घोषणा कर रही है। सूत्रों की मानें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सात लोकसभा सीटों में से चार सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जिनमें पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली सीट शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली शामिल हैं।

दिल्ली चलो मार्च टला, किसानों ने बनाया 4 दिनों का नया प्लान

नई दिल्ली। किसान नेताओं ने अब 29 फरवरी तक के लिए 'दिल्ली चलो' मार्च को टालने का ऐलान किया है। साथ ही घोषणा की है कि वे शनिवार को कैंडल मार्च निकालेंगे और 26 फरवरी को केंद्र सरकार का पुतला जलाएंगे। पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों ने अपने आंदोलन के अगले कदम पर चर्चा के लिए शुक्रवार शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) द्वारा यह निर्णय लिया गया। खनौरी में झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत और लगभग 12 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद किसान नेताओं ने बुधवार को 'दिल्ली चलो' मार्च दो दिनों के लिए रोक दिया था। अब उसी तारीख को और आगे बढ़ा दिया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली चलो मार्च को रोकने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति की घोषणा 29 फरवरी को की जाएगी। वहीं, एसकेएम (गैर-राजनीतिक) नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों पर शनिवार को किसान कैंडल मार्च निकालकर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और पूरे देश में शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी।

किसानों का प्रोग्राम

24 फरवरी- शाम को 21 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह और तीन अन्य किसानों की मौत पर श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा।

25 फरवरी- शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों को विश्व व्यापार संगठन की नीतियों से अवगत कराया जाएगा।

26 फरवरी- देशभर के गांवों में डब्ल्यूटीओ के पुतले जलाए जाएंगे और दोपहर 3 बजे के बाद दोनों सीमाओं पर पुतले जलाए जाएंगे।

27 फरवरी- एसकेएम (गैर राजनीतिक) की राष्ट्रीय समिति और किसान मजदूर संघर्ष समिति की दोनों सीमाओं पर बैठक होगी और अगले दिन उनकी संयुक्त बैठक होगी।

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी ममता, सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी टीएमसी

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने फिर से दोहराया है कि ममता बनर्जी की पार्टी राज्य की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। गौरतलब है कि बीते 24 घंटे के दौरान सूत्रों से यह जानकारी सामने आई थी कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में सीट बंटवारे को लेकर फिर से बातचीत का दौर शुरू हुआ है, जिससे कांग्रेस के लिए राहत माना जा रहा था। इसी दौरान, यह भी सामने आया कि ममता बनर्जी कांग्रेस को पांच सीटें दे सकती हैं। हालांकि, फिर यह भी दावा किया गया कि सिर्फ दो सीटें ही कांग्रेस को दिए जाने की बातें चल रही हैं। इन सबके बीच शुक्रवार रात फिर से कांग्रेस को झटका लगा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि कुछ हफ्ते पहले टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि टीएमसी राज्य की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा, असम और मेघालय की तुरा सीट पर भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इस स्थिति में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। टीएमसी सांसद के इस बयान से साफ है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी और राज्य की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी कर रही है। पिछले एक-दो दिनों में विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए कई तरह की सकारात्मक खबरें सामने आ रही थीं। पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यूपी में अलायंस फाइनल हुआ तो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात आदि के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी गठबंधन लगभग तय हो गया। 'आप' और कांग्रेस के बीच अगले 24 घंटे में गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। उधर, महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों का बंटवारा लगभग-लगभग तय हो गया है। ऐसे में भले ही कई दलों से गठबंधन फाइनल हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी का मैदान में अकेले उतरने से कांग्रेस को झटका लग सकता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सामना बीजेपी से है। पिछले लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को जहां 22 सीटें मिली थीं तो बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, वोट फीसदी में भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था। टीएमसी को 42 फीसदी और बीजेपी को 40 फीसदी वोट मिले थे। उधर, कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में महज दो सीटें ही जीत सकी थी। इसके अलावा, लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला था। लोकसभा चुनाव की घोषणा अगले महीने की जा सकती है।

सावधान जाहिर सूचना

ग्राम गोकन्या हल्का शिवनगर रा.नि.मं. सिमरोल तहसील महू जिला इन्दौर म.प्र खसरा न. 72 वा अन्य खसरो कृषि भूमि के सम्बन्ध मे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम गोकन्या हल्का शिवनगर रा.नि.मं. सिमरोल तहसील महू जिला इन्दौर म.प्र में स्थित कृषि भूमि विजय पिता राम भरोसे तिवारी से छल कर फरेब से सोची समझी चाल चल कर जिसका खसरा नंबर 72 वा अन्य खसरो को लिख कर 8 विक्रय पत्रो के लिए कूटरचित भाषा लिख कर दस्तावेज तयार कर वा फर्जी चेको को दे कर जालसाजी और 420 से विक्रय पत्रो का पंजीयन करवाया गया है इन सभी के नाम इस प्रकार है सुमित प्रकाश पाटनी पिता मणिक चन्द पाटनी, अरुणा पाटनी पति सुमित प्रकाश पाटनी,अनिल कुमार पंवार पिता मोहन सिंह पंवार, राहुल जैन पिता राकेश जैन, आनंद कसेरा पिता लक्ष्मणदास कसेरा राकेश जैन पिता स्व.नवीन चन्द जैन,पार्वती जैन पति बक्षीराम जैन, पवन जैन पिता बक्षीराम जैन इन सभी के खिलाफ पुलिस में जांच चल रही है कोर्ट में केस पेंडिंग है अतः कृषि भूमि खसरा नंबर 72 वा अन्य खसरो का सौदा किया गया था जिसका भुगतान राशि चेको के माध्यम से की गई थी पर चैक अनादरण होने से सौदा 2018 में निरस्त किया जा चुका है जिसकी सूचना पेपर विज्ञप्ति के माध्यम से पहले ही सूचना दी जा चुकी है अतः इन सभी विक्रय पत्रो के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति, संस्था या बैंक आदि से कर्ज हेतु प्राप्त करता है या इन रजिस्ट्री के माध्यम से विक्रय करता है तो इस की जवाब देयी किसान भूमि मालिक की नही होगी

अत: होने पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

सिंगल कॉलम

नौकरी के नाम पर नेटवर्क मार्केटिंग का जाल, आदिवासी अंचल के युवा निशाने पर

नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अब नौकरी देने के नाम पर युवाओं को जाल में फांस रही हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी बने इंदौर से भी ऐसी ठगी शुरू हो गई है। इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग कंपनी के प्रतिनिधि आदिवासी अंचल के युवाओं से नौकरी के नाम पर पैसा ऐंठ रहे हैं। कंपनी पहले नौकरी का आफर देती है। फिर ट्रेनिंग के नाम पर इंदौर बुलाकर हजारों रुपये जमा करवाती है। बात में अपने उत्पाद उन्हें देकर कहती है कि खरीदी करने और अन्य लोगों को जोड़ने पर पैसा दिया जाएगा। एक के बाद एक कई शिकायतें पुलिस तक भी पहुंचने लगी है। हालांकि अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र के दत्तनगर में आफिस व ट्रेनिंग सेंटर बनाकर पैसा ऐंठने के ऐसे काम को अंजाम दिया जा रहा है। कंपनी को रुपया देकर उलझने वालों में ज्यादातर छात्र है इनमें भी लड़कियां ज्यादा है। इंदौर से दूर रहने वाले इन युवाओं को एजेंट पहले अच्छे वेतन की नौकरी देने का लालच देते हैं। ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने व इंदौर आने की बात कही जाती है। फिर इनसे 15 हजार से 45 हजार रुपये तक लिए जाते हैं। दो-चार दिन की ट्रेनिंग के दौरान इनसे कंपनी का सदस्य बनने के कागज पर हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। कंपनी के पोर्टल से खरीद के लाभ समझाए जाते हैं और उत्पाद दे दिए जाते हैं। उन पर दी गई छूट को ही कमाई करार दे दिया जाता है। बाद में युवा वेतन और अपने रुपये की मांग करते हैं तो इनसे कहा जाता है कि इसी तरह वे दूसरे लोगों को अपने से जोड़े और उनको कंपनी के उत्पाद दिलवा दें तो इससे कमाई होगी।

इंदौर की पाश कालोनी में इंडियन आइल के मैनेजर के घर डाका

इंदौर। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद आमजन यह उम्मीद कर रहे थे कि इंदौर में गंभीर अपराधों से राहत मिलेगी लेकिन अपराधी बेखौफ गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रवार तड़के पाश कालोनी में हथियारबंद बदमाश इंडियन आइल कार्पोरेशन (आइओसी) के मैनेजर के यहां दरवाजे का लाक तोड़कर घुसे और परिवार को बंधक बनाकर सोने-चांदी के जेवर व नकदी लूट लिया।बाद में बदमाश उनकी कार लेकर भाग निकले। घटना के बाद पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज से जांच में जुट गई। कार में लगे फास्टैग से पता चला कि डकैत धार की तरफ भागे हैं। डकैत डंडे, पाइप और पत्थर लेकर आए थे। शहर में 12 दिनों में डकैती की दूसरी वारदात हुई है। घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र (सांवेर रोड) स्थित लंदन विला टाउनशिप में तड़के करीब साढ़े चार बजे की है। बंगला नंबर 48 में रहने वाले पुष्पेंद्रसिंह के घर चार नकाबपोश घुसे। प्रथम मंजिल पर अलमारियां खंगालीं और सीधे बेडरूम में घुस गए। पुष्पेंद्र रविंद्रपाल सिंह पत्नी आकांक्षा, बेटे कननसिंह और नंदनसिंह के साथ सो रहे थे। बगैर शोर किए बदमाशों ने अलमारियों की तलाशी लेनी शुरू कर दीं। पुष्पेंद्र जागे और बदमाशों को ललकारा तो पाइप, डंडे लेकर टूट पड़े। उन्हें धमकाते हुए कहा कि डकैती करने आए हैं। हमें हमारा काम करने दो, वरना मारेंगे। आकांक्षा ने डरते हुए कहा कि मारपीट मत करो। आपको जो सामान चाहिए निकाल लो। इसके बाद एक डकैत उनके पास खड़ा रहा और तीन ने सोने के गहने और नकदी निकाल ली। करीब पौन घंटे तक पूरे घर में तलाशी ली और जाते-जाते बाहर खड़ी पुष्पेंद्र की कार (एमपी09-सीटी-7446) लेकर फरार हो गए। पुष्पेंद्र आइओसी (मांगलिया) और आकांक्षा आइओसी (एयरपोर्ट) पर मैनेजर हैं। उन्होंने मोबाइल से काल लगाने की कोशिश भी लेकिन डकैतों ने पीटकर मोबाइल छीन लिया। मोबाइल बाहर फेंक देंगे, घंटी बजाकर ढूंढ लेना बदमाशों ने पुष्पेंद्र और आकांक्षा के मोबाइल कब्जे में कर लिए। आकांक्षा के मुताबिक आरोपितों से फोन व दस्तावेज लौटाने के लिए कहा तो एक डकैत ने कहा डाक्यूमेंट्स नहीं लेंगे। मोबाइल भी बाहर फेंक देंगे। जाने के बाद घंटी बजाकर ढूंढ लेना। जाते-जाते डकैतों ने पासपोर्ट दिखाए और कहा- देख लो इन्हें हम नहीं ले जा रहे हैं। आरोपित बाहर गार्डन के पास दोनों मोबाइल फेंक गए थे। जाते समय दरवाजे का हैंडल भी बाहर रस्सी से बांधकर बंद कर गए थे।

कमेंट्स करने पर भीड़े इंदौर के एसजीएसआईटीएस के छात्र, जमकर मारपीट

शहर के प्रतिष्ठित गोविंदराम सेकसरिया इंजीनियरिंग कालेज (जीएसआईटीएस) में जूनियर और सीनियर छात्रों के दो गुट आमने-सामने हो गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक छात्र को शराब की बोतल लगी है। उसकी आंख पर चोट है।घटना शुक्रवार देर रात की है। घायल छात्र प्रियांशु राठौर (द्वितीय वर्ष) अपने पांच दोस्तों के साथ कालेज के बाहर पान की दुकान पर खड़ा था। वहां से सीनियर (फ़ाइनल) के छात्र गुजरे तो उसने कुछ कमेंट्स की। सीनियर में कहा तू हमारे सामने कैसे बोल सकता है। विवाद किया और होस्टल से फोर्थ, थर्ड और सेकंड ईयर के क़रीब दो सौ छात्र लेकर आ गया। दोनों पक्षों में खूब विवाद हुआ। हालांकि पुलिस और फ़ेकल्टी ने समझा दिया। थोड़ी देर बाद प्रियांशु दोस्त विकास के साथ मालवा मिल की तरफ़ जा रहा था तो वापस भीड़ गए। क़रीब पच्चीस लड़कों ने मारपीट की। विकास को पीटा और कांच की बोतल मार दी। शराब के नशे में थे छात्र पान की दुकान से विवाद की शुरुआत हुई। विवाद करने वाले छात्र शराब के नशे में थे। डे-स्कालर और होस्टलर आपस में विवाद करते रहे है और कालेज प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया।

नर्मदा के चौथे चरण को मिली सैद्धांतिक सहमति

सिटी चीफ इन्दौर

इंदौरियों के लिए राहतभरी खबर है कि नर्मदा नदी के पानी के चौथे चरण के लिए भेजी गई विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को केंद्र और राज्य सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। करीब 15 दिन में 1200 करोड़ रुपये की इस योजना के लिए निविदा जारी कर दी जाएगी।नर्मदा का चौथा चरण इंदौर आने के बाद शहरवासियों को प्रतिदिन पानी मिलने लगेगा। चौथे चरण को इंदौर लाने की योजना करीब 1700 करोड रुपये की है। इसमें से पहले चरण में 1200 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए जाएंगे। इस राशि में से 17 प्रतिशत राशि नगर निगम को वहन करना होगी। 25 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में राज्य शासन से मिलेगा जबकि 58 प्रतिशत खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। शहर में नई टंकियों का निर्माण, वितरण लाइन इत्यादि डालने के लिए नगर निगम को अलग से करीब 600 करोड़ रुपये लगेंगे। इस खर्च की व्यवस्था निगम बैंकों से ऋण लेकर करेगा। वर्तमान में इंदौर में प्रतिदिन करीब 436 एमएलडी जल वितरित होता है। इसमें नर्मदा के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के तहत 406 एमएलडी तथा यशवंत सागर से 30 एमएलडी पानी मिलता है। नर्मदा का चौथा चरण आने के बाद शहर को प्रतिदिन

अतिरिक्त 400 एमएलडी पानी मिलने लगेगा। मतलब यह हुआ कि चौथे चरण का काम पूरा होने के बाद शहर को रोजाना करीब 836 एमएलडी जल वितरण के लिए उपलब्ध होगा। शहरभर में डायरेक्ट सप्लाई बंद हो जाएगी और टंकियों से ही जल वितरण किया जाएगा। चौथा चरण आने के बाद शहर में प्रतिदिन जल वितरण की योजना भी है। 32 टंकियों का निर्माण होगा, नया ट्रीटमेंट प्लांट भी बनेगा शहर में वर्तमान में 106 टंकियां हैं। नर्मदा के चौथे चरण के तहत 32 नई टंकियों का निर्माण भी किया जाना है। हालांकि यह काम दूसरे चरण में होगा। 1200 करोड़ रुपये की जो निविदा जारी की जाना है उसमें नर्मदा किनारे नया इंटेकवेल, रा वाटर लाइन, 22 किमी लंबी पंपिंग मेन क्लियर वाटर लाइन, फीडर लाइन, बुस्टिंग पंपिंग स्टेशन, ग्रेविटी लाइन डाली जाना है। इसके अलावा नया ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। इस निविदा में उल्लेखित काम पूरा होने के बाद इंटेकवेल से राऊ तक का काम पूरा हो जाएगा। इसके आगे का काम नगर निगम को खुद के खर्चे पर करना होगा।

भक्ति के बीज बचपन में ही डालें, पचपन में नहीं

सिटी चीफ इन्दौर

भक्ति किसी भी रूप में हो उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। विडंबना है कि हमें वृद्धावस्था में ही भक्ति का जुनून चढ़ता है। यदि बाल्यकाल से ही भक्ति के संस्कार मिले तो वृद्धावस्था संवर जाती है। भक्ति के बीज बचपन में ही डालें पचपन की उम्र में नहीं। भक्ति में निष्काम भाव होना चाहिए। भक्ति में पाखंड या प्रदर्शन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता।यह बात बाल व्यास आचार्य पंडित ऋषभदेव ने कही। वे श्रीजी वेली, बिचौली मर्दाना पर चल रहे भागवत ज्ञान यज्ञ में उपस्थित भक्तों को बालक ध्रुव की भक्ति पर संबोधित कर रहे थे। प्रारंभ में व्यासपीठ का पूजन वार्ड 76 की पार्षद सीमा सोलंकी, संयोजक नितिन मालवीय, महेंद्र शुक्ला, अजय पांडे, कनक मालवीय, आशुतोष अग्रवाल, रोहित पाठक आदि ने किया। संयोजक नितिन मालवीय ने बताया कि पंडित ऋषभदेव 27 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 से 5 बजे तक व्यासपीठ पर विराजित होकर कथामृत की वर्षा करेंगे। भक्ति गृहस्थ होते करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण विद्वान वक्ता ने कहा कि हम सबके जीवन में सुरुचि और सुनीति का संशय बना रहता है। इसी कारण हम सब अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। भगवान की भक्ति का मतलब यह नहीं है कि हिमालय पर चले जाएं या गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी से पलायन कर लें। भक्ति गृहस्थ होते हुए करना ज्यादा चुनौती पूर्ण काम है। गृहस्थ जीवन तो सबसे बड़ा धर्म माना गया है। प्रेम, दया, करुणा, सत्य जैसे गुणों का सृजन भक्ति मार्ग से ही संभव है। भारत भूमि को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान इसलिए मिला, क्योंकि यह भक्तों की ही भूमि रही है जिसमें जितने भक्त हुए उतने कहीं और किसी देश में नहीं हुए।

सावधान...हाईटेक हो गए है वाहन चोर लक्जरी कार को मिनटों में कर लेते है हैक

सिटी चीफ इन्दौर

शहर की पाश कालोनी महालक्ष्मी नगर में वाहन चोरों की एक टोली मिनटों में लक्जरी कार लेकर फरार हो गई। चोरों ने कार का न कांच फोड़ा, न डुप्लीकेट चाबी लगाई, बल्कि कार का सिस्टम ही हैक कर लिया। पूरी वारदात का सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी सामने आया है। बदमाश साफ्टवेयर और लेपटाप लेकर आए थे। इस घटना से जांच एजेंसियां भी चौंक गई हैं।कालोनी के आर सेक्टर में रहने वाले सरकारी ठेकेदार विनोदसिंह राजावत ने अपनी फार्च्यूनर कार (एमपी 09जेई 4610) घर के बाहर पार्क कर दी थी। कालोनी में घरों के बाहर कई गाड़ियां खड़ी हुई थी। रातभर चहल पहल भी बनी रहती है। इसके बावजूद चोर आसानी से कार चुरा कर ले गए। विनोदसिंह ने जब सीसीटीवी फुटेज निकाले तो देखा उनकी कार के समीप एक सफेद रंग की दूसरी कार आकर रुकी है। उस कार में बैठे बदमाश कुछ देर रुके और विनोदसिंह की कार की लाइट जलने लगी। आनलाइन मिल रहे डिवाइस से चोरी हो

रही लक्जरी कारें कार हैक करने वाली डिवाइस ई-कामर्स वेबसाइट पर आसानी से मिल रही है। कार चोर रिमाट कंट्रोल वाली कार की चाबी से निकलने वाले कोड को डी-कोड कर कार के पास बैठे हैकर्स के लेपटाप पर भेजती है। हैकर कार का रिमोट एक्सेस कर लेता है। कार मालिक की चाबी निष्क्रिय हो जाती है। कार का इंजिन स्टार्ट हो जाता है और हैकर कार अपने नियंत्रण में ले लेता है।

पांच बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो लाइसेंस निरस्त होगा

सिटी चीफ इन्दौर

इंदौर को यातायात में नंबर वन बनाने की कवायद के तहत बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले आदतन वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती बरती जाए। महापौर ने बताया-यह बात सामने आई है कि ई-चालान को लेकर लोग गंभीर नहीं हैं। वे ई-चालान जमा ही नहीं करते और नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। ऐसे आदतन लोगों के सख्ती बरती जाएगी। पांच बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने और ई-चालान जमा नहीं करने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। ऐसे लोगों की सूची भी तैयार कर ली गई है। जल्द ही कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी।यह बात महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्मार्ट सिटी कार्यालय में शुक्रवार को हुई बैठक में कही। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, आरटीओ प्रदीप कुमार शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। महापौर ने बताया कि बैठक में नेहरू स्टेडियम के स्थान पर नया स्टेडियम निर्माण को लेकर भी चर्चा हुई है। कंसल्टेंट ने जो प्लान दिया है, हमने उसमें कुछ सुझाव और संशोधन दिए हैं। बैठक में वर्षाकाल से पहले मध्य क्षेत्र के ड्रेनेज और अन्य कार्य पूरे करने के निर्देश भी दिए गए। वन-वे का उल्लंघन करने वालों पर आज से कार्रवाई ः जवाहर मार्ग, एमजी रोड और राजवाडा क्षेत्र को वन-वे

घोषित करने के संबंध में शुक्रवार को ही नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब इन मार्गों पर वन-वे का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शनिवार से यातायात विभाग चालानी कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि शहर के यातायात को सुचारु बनाने के उद्देश्य से करीब एक माह पहले जवाहर मार्ग के संजय सेतु से राजमोहल्ला चौराहा तक के हिस्से और एमजी रोड के बड़ा गणपति से कृष्णपुरा छत्रियों तक के हिस्से को वन-वे घोषित किया था। बावजूद इसके वाहन चालक इसका पालन नहीं कर रहे थे। पुलिसकर्मियों को दिनभर व्यवस्था बनाए रखने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी। जगह-जगह बेरिकेडिंग कर लोगों को समझाइश भी दी जा रही थी। निगम मुख्यालय की सात दशक से ज्यादा पुरानी इमारत तोड़कर नई बनेगी ः नगर निगम मुख्यालय की सात दशक से ज्यादा पुरानी इमारत जमींदोज कर उसके स्थान पर कार्पोरेट कार्यालय की तर्ज पर नई इमारत बनाई जाएगी। इस इमारत में अत्याधुनिक लाइब्रेरी और कैंटीन की व्यवस्था भी रहेगी। अधिकारियों के कार्यालय हाईटेक और सुसज्जित होंगे। नई इमारत कितनी मंजिला होगी, यह फिलहाल तय नहीं है लेकिन इतना जरूर होगा कि इसमें निगमकर्मियों और आमजन की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जल्दी ही इस संबंध में कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा निगम की अधूरी पड़ी इमारत का बचा हुआ काम भी तेजी से किया जाएगा। भार्गव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भी इंदौर यात्रा के दौरान नगर निगम के लिए अत्याधुनिक भवन की बात कही थी। उन्होंने परिषद सभागृह के लोकार्पण समारोह में निगम को 50 करोड़ रुपये निर्माण के लिए देने की घोषणा भी की थी। मुख्यालय की इमारत दशकों पुरानी होकर जीर्णशीर्ण हो रही है। हर कोई चाहता है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर का निगम मुख्यालय अत्याधुनिक हो।

उज्जैन व्यापार मेले के लिए इंदौर में खरीदार आगे बढ़ा रहे वाहनों की बुकिंग

सिटी चीफ इन्दौर

इंदौर से महज 70 किमी दूर उज्जैन में पहली बार व्यापार मेला आयोजित हो रहा है। इसमें ग्वालियर मेले की तरह ही वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसका असर इंदौर में वाहनों की बुकिंग पर भी देखा जा सकता है। खरीदार खासकर महंगी कार खरीदने वाले वाहनों की बुकिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि व्यापार मेले में टैक्स छूट का लाभ लिया जा सके।प्रदेश में सर्वाधिक वाहनों की बिक्री इंदौर में होती है। इंदौर परिवहन कार्यालय द्वारा भी प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व एकत्रित किया जाता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले वाहनों की बिक्री और राजस्व दोनों उज्जैन मेले के कारण प्रभावित होने वाले हैं। पहली बार उज्जैन में होने वाले व्यापार मेले को लेकर इंदौर के लोग भी उत्साहित है। टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए लोगों ने वाहन खरीदने की योजना को आगे बढ़ा दिया है। क्रेटा कार खरीदार मनीष विश्वकर्मा का कहना है कि जनवरी में क्रेटा कार खरीदने वाले थे। व्यापार मेला आयोजित होने की जानकारी मिलने से खरीदी की योजना को एक माह आगे बढ़ा दिया। इसी तरह राजेश पटेल ने भी फार्च्यूनर गाड़ी व्यापार मेला से खरीदने का

निर्णय लेते हुए मार्च में बुकिंग कराने का निर्णय लिया है। मार्च में तीन गुणा बढ़ेगी कारों की खरीदी कार शोरूम के मैनेजर आदर्श मिश्रा का कहना है कि फरवरी में कई लोगों ने बुकिंग को मार्च तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। अभी से लोग उज्जैन मेले के लिए कार की बुकिंग करवा रहे है। उज्जैन के साथ ही इंदौर के शोरूम संचालकों ने मेले के लिए पंजीयन कराया है। मार्च में कार की खरीदी में तीन गुणा के करीब उछाल आने की संभावना है। उज्जैन परिवहन विभाग में होंगे पंजीकृत व्यापार मेले से वाहन खरीदने पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए वाहन का पंजीयन उज्जैन परिवहन कार्यालय में कराना होगा। इसके बाद हमेशा के लिए वाहन उज्जैन पासिंग रहेगा, लेकिन प्रदेश में कही भी वाहन का नामांतरण, ट्रांसफर जैसे कार्य कराए जा सकेंगे। इंदौर के सैकड़ों वाहन अब तक छूट के लिए ग्वालियर में पंजीकृत होते थे।

चिंता की बात, गर्मी की आमद से पहले ही कम होने लगा तालाबों का जलस्तर

गर्मी की आमद से पहले ही शहर के तालाबों का जलस्तर कम होने लगा है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल पर्याप्त पानी उपलब्ध है। चिंता इस बात की है कि धूप के तेवर अगर बहुत ज्यादा तीखे रहे तो तालाबों का कंठ तेजी से सूखने लगेगा।ऐसे में शहर में जलसंकट से इनकार नहीं किया जा सकता। नगर निगम शहर में फिलहाल 150 से ज्यादा टैंकर चलवा रहा है। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाने की बात भी की जा रही है। पिछले वर्ष भी नगर निगम ने 300 से ज्यादा टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की थी। जुलाई के अंत तक शहर में टैंकर चले थे। इस वर्ष भी ऐसी ही आशंका है। किराए के 70 टैंकर से जलापूर्ति नगर निगम फिलहाल शहर में 157 टैंकरों के माध्यम से उन क्षेत्रों में जलापूर्ति कर रहा है जहां नर्मदा लाइन नहीं है या जहां पर्याप्त जल सप्लाई नहीं हो रही। निगम के पास खुद के 87 टैंकर हैं। शेष 70 टैंकर किराए के हैं। नगर निगम हर वर्ष टैंकर पर किराए के रूप में लाखों रुपये खर्च करता है।

आपकी गाड़ी से नींद उड़ जाती है बोलकर-रहवासियों ने बंद करवाई पुलिस गश्त

सिटी चीफ इन्दौर

बाणगंगा थाना क्षेत्र की लंदन विला 120 बंगलों की टाउनशिप है। कालोनी में ज्यादातर नौकरीपेशा लोग रहते हैं। चारों तरफ से कवर्ड इस टाउनशिप में रहवासियों ने गार्ड तो रखे हैं लेकिन कुछ लोग रात्रि में गश्त के दौरान उनके सीटी बजाने पर आपत्ति लेते थे। नींद खराब होने का बोलकर सीटी बजाना बंद करवा दिया गया। कुछ समय पहले तक पुलिस की गाड़ी भी कालोनी में गश्त के लिए आती थी लेकिन उन्हें भी रहवासियों ने मना कर दिया।लंदन विला में वारदात के बाद रहवासी डरे हुए हैं। बदमाश परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। वारदात के बाद एकत्र हुए रहवासियों ने खुद माना कि सुरक्षा में चूक हुई है। बाणगंगा थाने के पुलिसकर्मी पहले नियमित रात्रि गश्त करते थे लेकिन लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई। इसी तरह गार्ड को भी सीटी बजाने से मना करवा दिया। उधर, पुलिस की जांच में पता चला बदमाश कालिंदी गोल्ड सिटी की तरफ से घुसे थे। दीवार कूदकर अंदर आए बदमाशों ने सर्वप्रथम ईडब्ल्यूएस में चोरी का प्रयास किया। यहां नीचे और प्रथम मंजिल पर घूमते रहे। कीमती सामान न मिलने पर पुष्पेंद्र के मकान में घुस गए। सूना मकान समझकर दरवाजे का लाक

तोड़ा और सीधे पहली मंजिल पर जा पहुंचे। कालोनी के खुले एरिया के पास की बाउंड्रीवाल भी छोटी और कमजोर है, संभवतः इसी का फायदा उठाकर बदमाश आसानी से भीतर घुस गए। गार्ड से एक दिन पूर्व पूछा-48 नंबर बंगला कहां है पुलिस का अनुमान है कि बदमाशों ने रैकी कर वारदात की है। एक दिन पूर्व भी बदमाश आए थे। गार्ड से बंगला नंबर-48 का पूछा था। टीआइ नीरज बिरथरे के मुताबिक दंपती कुछ दिनों से बाहर थे। चोरों ने सूना घर समझ कर सेंध लगाई और अचानक सामना हो गया। कालोनी में कुछ दिनों पूर्व गैस पाइप लाइन का काम भी हुआ है। कालोनी में तीन दिन तक मजदूर रहे थे। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। 12 दिन पूर्व हुई डकैती में खाली हाथ पुलिस कनाड़िया थाना क्षेत्र में भी 12 दिन पूर्व नकाबपोश बदमाश डकैती कर चुके है। डकैतों ने थाने के सामने ही तिलकनगर (बी) में बैंड संचालक वकील दांगी के घर में घुसकर पत्नी व बच्चों से मारपीट कर आभूषण और नकदी लूट ली लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले में खाली हाथ है। दहशत के वह सात मिनट बेडरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की गतिविधि रिकार्ड हो गए है। दंपती को धमकाते हुए और ज्वेलरी-नकदी का पूछते हुए भी सुनाई दे रहे है। इस दौरान मैनेजर दंपती दो बच्चों को लेकर डरकर गुमसुम बैठे हुए है। बातचीत के अंश डकैतः सोना-चांदी कहां पर रखा है। आकांक्षा ः भैया रखते नहीं हैं। सामने लाकर है। लाकर में हजार-दो हजार रुपये मिलेंगे। पुष्पेंद्र- हम लोग बाहर रहते है इसलिए घर में नहीं रखते। घर में मेड रहती है। डकैतः ये क्या। आकांक्षाः भैया बाइयां काम करती हैं। पुष्पेंद्रः मोबाइल और डाक्यूमेंट्स को हाथ मत लगाना। डकैतः मोबाइल नहीं लेकर जाएंगे। उठाना मत और चिल्लाना मत। बेडशीट ओढ़कर सो जाओ, वरना बहुत बुरा पीटेंगे मैं नींद में थी। डकैत पुष्पेंद्र (पति) को पीटने लगे। नींद खुली तो मैं बचाओ-बचाओ चिल्लाने लगी। डकैतों ने कहा- चुपचाप सो जाओ। बेडशीट ओढ़ लो, वरना हम तुम्हें पीटेंगे। पति-पत्नी बच्चों को लेकर चुप हो गए। डकैतों से कहा-मारपीट मत करो। एक डकैत ने साथियों से कहा- बच्चे भी हैं, मारपीट मत करो। डकैतों को अलमारियों में ज्यादा कुछ नहीं मिला। थोड़ी ज्वेलरी और विदेशी व भारतीय मुद्रा मिली। उन्होंने पुष्पेंद्र और मुझसे हाथ में पहनी अंगूठियां भी उतरवा लीं। डकैतों ने कहा कि चुपचाप सोते रहना। हमारे जाने पर शोर मत करना। डकैतों में तीन कम बोले। एक ही बात कर रहा था। बातचीत से पढ़ा-लिखा लग रहा था।

टूटकर बिखर गई भदभदा बस्ती, बिलखते रह गए बेबस, तीन दिन में 268 मकान जमींदोज

सिटी चीफ भोपाल।
आंखों के सामने ईंट-ईंट करके जोड़ा सपनों का आशियाना उजड़ गया, बेबस बिखलते रह गए, आंसू पौंछते हुए अपना समान समेटते हुए बस व्यवस्था को कोसते रहे। होटल ताज के सामने भदभदा बस्ती में शुक्रवार को नगर निगम ने 129 मकानों पर बुलडोजर चलाया। तीन दिन शुक्रवार को 386 में से 268 मकानों को जमींदोज किया गया। वहीं बचे हुए 118 परिवारों से भी सहमति मिल गई है। शनिवार को इनके मकानों को भी गिरा दिया जाएगा। इधर कार्रवाई के विरोध में रहवासी मानव अधिकार आयोग भी पहुंच गए हैं और निगम प्रशासन के द्वारा की जा रही मनमानी की शिकायत की है।दस दिन पहले से बिजली, पानी की सप्लाई बंद बता दें कि बस्ती क्षेत्र में जब से कार्रवाई शुरू की गई है, तब से यहां रहने वालों के घरों में चूल्हा नहीं सुलगा है। प्रशासन ने 10 दिन पहले बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी थी।

जबकि बुधवार से बस्ती में जाने वाले रास्तों पर पुलिस की बैरिकेटिंग है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जा रहा।

प्रशासन सुनने को नहीं तैयार

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह और नगर निगम कमिश्नर फ्रैंक नोबल ए का रहवासियों से कहना था कि बीते 24 जुलाई 2023 को शपथ पत्र देकर दिसम्बर 2023 तक का समय मांगा गया था, जो बीत चुका है। इसलिए अब हर हाल में कार्रवाई होगी। हालांकि कार्रवाई के विरोध में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रशासन ने रहवासियों को वैकल्पिक आवास देने को कहा। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई।

तीन घंटे में गिराए 129 मकान

बुधवार सुबह छह बजे से ही बस्ती में बुलडोजर चलने शुरू हो गए। करीब तीन घंटे में ही यहां 129 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। दिनभर रहवासी अपना-अपना सामान समेटते रहे। शाम पांच बजे अधिकारी बस्ती से बाहर निकल गए। जो मकान बच गए हैं, उनके रहवासियों से कहा है कि शनिवार की सुबह सभी मकान खाली मिलना चाहिए।

मानव अधिकार आयोग पहुंचे रहवासी

शुक्रवार को रहवासी मानव अधिकार आयोग पहुंचे। जहां उन्होंने कलेक्टर, निगम कमिश्नर, एसडीएम, अपर आयुक्त और अधीक्षण यंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में रहवासियों ने प्रशासन पर जीवन के मौलिक अधिकार, भोजन, शिक्षा, काम, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकारों को छिनने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया कि प्रशासन ने ३सुविधाओं से वंछित करते हुए बिना सूचना, बिना विस्थापन किए बच्चों को परीक्षा से वंचित किया।

टीबी के मरीज ने कमरे में लगाई फांसी, घरवालों से अलग रहता था

राजधानी के बैरागढ़ थाना इलाके में किराए के कमरे में अकेले रहने वाले एक युवक ने फांसी लगा ली। घटना गुरुवार दोपहर की है। तपेदिक (टीबी) की बीमारी के कारण वह घर से अलग रहने लगा था। उसका भाई उसे कमरे पर खाना देने पहुंचा, तो उसे फंदे पर लटका देखा। पुलिस ने मर्ग कायम कर छानबीन शुरू कर दी है। मृतक के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि संभवत~ बीमारी के साथ अकेलेपन के तनाव के कारण उसने इस तरह का कदम उठा लिया होगा। पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है।बैरागढ़ थाना पुलिस के मुताबिक कुम्हारपुरा निवासी 30 वर्षीय जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र छोटेसिंह

यादव कैटरिंग का काम करता था। टीबी की बीमारी से ग्रस्त होने के बाद उसका काम छूट गया था। घर में संक्रमण ना फैले, इस वजह से वह परिवार से अलग एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा था। उसका छोटा भाई लक्की यादव उसे कमरे पर खाना देकर आता था। गुरुवार दोपहर करीब ढाई बजे लक्की खाना लेकर जितेंद्र के कमरे पर पहुंचा था। उसने देखा कि भाई ने फांसी लगा ली थी। जितेंद्र की शादी नहीं हुई थी।

सप्ताह में एक दिन बगैर बस्ते के लगेंगी कक्षाएं

दूसरी कक्षा तक के बच्चों को नहीं मिलेगा होमवर्क मध्यप्रदेश में स्कूल बैग पॉलिसी लागू

सिटी चीफ भोपाल।
प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन बिना स्कूल बैग के कक्षाएं लगाई जाएगी। दूसरी कक्षा तक के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए शासन ने स्कूलों में बस्ते का वजन तय कर दिया है। इसके संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने 2022 में आदेश जारी किए थे।अब नए शैक्षणिक सत्र से सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।बता दें, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। इसके तहत स्कूलों में बस्ते के वजन को कम करना है। बस्ते को वजन को कम करने के लिए करीब दो साल पहले सितंबर 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसका स्कूलों में पालन नहीं किया जा रहा है।नवीन दिशा-निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने जारी किए हैं। विभाग ने आदेश में कहा है कि विद्यार्थी के बस्ते का वजन निर्धारित सीमा में ही है इसके लिए जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक तीन माह में शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों के स्कूल बैग की जांच कराएंगे। पढ़ाई के घंटे तय किए गए हैं विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई के घंटे भी तय किए है। दूसरी तक के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा।तीसरी से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह दो घंटे, छठवीं से आठवीं तक प्रतिदिन एक घंटे और नौवीं से

12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन दो घंटे का ही होमवर्क दिया जाएगा। वजन का नोटिस बोर्ड पर चार्ट लगाना होगा अनिवार्य प्रत्येक स्कूल को नोटिस बोर्ड एवं कक्ष में बस्ते के वजन का चार्ट प्रदर्शित करना होगा। स्कूल डायरी का वजन भी बस्ते के वजन में ही शामिल किया गया है। साथ ही शाला प्रबंधन समिति के द्वारा ऐसी समय-सारणी तैयार की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को प्रतिदिन सभी पुस्तकें/ अभ्यास पुस्तिकाएं/ कापियां नहीं लानी पड़े और बस्ते का वजन निर्धारित सीमा से अधिक न हो।शाला प्रबंधन द्वारा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं, वर्क बुक एवं अन्य आवश्यक सामग्री को स्कूल में ही रखने की व्यवस्था करना होगी। कंप्यूटर, नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा खेल एवं कला की कक्षाएं बिना पुस्तकों के ही लगाई जाएगी।

बड़ी झील में मिला युवक का शव, दो दिन से था लापता

सिटी चीफ भोपाल।
बड़ा तालाब में राजा भोज की प्रतिमा के पास से शुक्रवार सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। उसकी पहचान होने के बाद पता चला कि वह दो दिन से लापता चल रहा था। स्वजन ने निशातपुरा थाने में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करा रखी थी। पुलिस के मुताबिक प्रथमदृष्टया यह खुदकुशी का मामला लगता है। पुलिस ने मर्ग कायम कर छानबीन शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है।कोहेफिजा थाना पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह बड़ा तालाब से एक युवक का शव पानी से बाहर निकाला गया। उसकी पहचान निशातपुरा के जनता नगर में रहने वाले 24 वर्षीय बाबर खान के रूप में हुई। वह करोंद मंडी में व्यापार करता था। वह 21 फरवरी को तड़के तीन बजे घर में बिना कुछ बताए स्कूटर से कहीं चला

गया था। जब वह दिनभर घर नहीं लौटा तो स्वजन ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उसकी पत्नी ने निशातपुरा थाने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। तलाशी में कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने के कारण खुदकुशी की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। बाबर के परिवार में पत्नी के अलावा छोटे चार बच्चे हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल भोपाल में

प्रबुद्धजन सम्मेलन को करेंगे संबोधित तैयारियों में जुटा संगठन

सिटी चीफ भोपाल।
केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को मप्र के दौरे पर आ रहे हैं। वह भोपाल में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित सम्मेलन में तीन लाभार्थी परिवारों से भी संपर्क करेंगे। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, लोकसभा प्रभारी डा. महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी एवं प्रदेश प्रवक्ता मिलन भार्गव उपस्थित रहे। तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक भी आयोजित की गई। इसमें सभी मोर्चा प्रकोष्ठों और प्रदेश पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आयोजन में

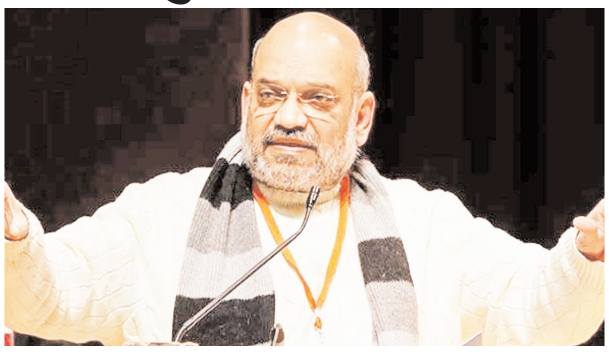

किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे।केंद्रीय गृहमंत्री शाह भोपाल के अलावा ग्वालियर और खजुराहो भी जाएंगे। भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में ग्वालियर और खजुराहो और की बैठक व सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की गई। बता दें कि अमित शाह 25 फरवरी को ही ग्वालियर में ग्वालियर-चंबल क्लस्टर के चारों लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना की प्रबंध समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर तीन बजे खजुराहो में लोकसभा के बूथ समिति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम छह बजे भोपाल में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संत गाडगे महाराज की मनी जयंती भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रदेश प्रभारी डा. महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में संत गाडगे महाराज की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश महांमत्री व विधायक भगवानदास सबनानी, प्रदेश कार्यालय मंत्री डा राघवेंद्र शर्मा ने भी संत गाडगे को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

रवींद्र भवन में सदाबहार फिल्मी गीतों से गुलजार होगी शाम, जनजातीय संग्रहालय में देखें चित्र प्रदर्शनी

सिटी चीफ भोपाल।
शहर में कलात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक, खेल, धार्मिक आदि गतिविधियों का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। शनिवार 24 फरवरी को भी शहर में ऐसी अनेक गतिविधियों का आयोजन होने जा रहा है, जिनका आप आनंद उठा सकते हैं। यहां हम कुछ ऐसे ही चुनींदा कार्यक्रमों की जानकारी पेश कर रहे हैं, जिसे पढ़कर आपको अपनी दिन की कार्ययोजना बनाने में आसानी होगी।सत्संग समागम - भेल जंबूरी मैदान पर उज्जैन से आए संत बाबा उमाकान्त महाराज अपने प्रवचन के जरिए लोगों को शाकाहारी, सदाचारी और नशा मुक्त रहने की प्रेरणा देंगे और उन्हें ईश्वरवादी धर्मपरस्त बनने की राह दिखाएंगे। सत्संग सुबह 11 बजे से शुरू होगा। माह का प्रादर्श - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में फरवरी माह के प्रादर्श के रूप में भूटिया समुदाय के आध्यात्मिक उपकरण फुरबा को प्रदर्शित किया जा रहा है। वीथि संकुल में इसे सुबह 11

बजे से शाम छह बजे तक देखा जा सकता है। विज्ञान दिवस समारोह - आंचलिक विज्ञान केंद्र में चल रहे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह में डेटाइम एस्ट्रोनोमी के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। समय दोपहर 12 बजे से एक बजे तक है। चित्र प्रदर्शनी - मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय की लिखंदरा दीर्घा में गोंड चित्रकार संतू तेकाम के चित्रों की प्रदर्शनी सह-विक्रय का संयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी को दोपहर 12 बजे से रात आठ बजे तक देखा जा सकता है। साहित्य सम्मेलन - साहित्यिक संस्था अंतरराष्ट्रीय मैत्री मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन एवं हेमंत स्मृति पुरस्कार समारोह दोपहर डेढ़ बजे से होटल पलाश में होने जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं के साहित्यकारों के अलंकरण के साथ ही कविता पाठ के सत्र भी होंगे। शुभारंभ सत्र की मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री मेहरुनिसां परवेज होंगी तथा अध्यक्षता वरिष्ठ कवि राजेश जोशी करेंगे। शाम के सत्र में कविता पाठ होगा। विरासत हैंडलूम प्रदर्शनी - त्रिलंगा स्थित पुराने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय परिसर में विरासत हैंडलूम प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 25 फरवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में महिलाओं के समूहों द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प एवं हाथकरघा उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। प्रदर्शनी में प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के 20 से अधिक बुनकर अपने उत्पाद लेकर आए हैं। गीत गुंजन - गीत गुंजन फाउंडेशन की ओर से सदाबहार फिल्मी गीतों की शाम गीत गुंजन का आयोजन रवींद्र भवन में किया जा रहा है। इस मौके पर शहर के गायक कलाकार प्रस्तुति देंगे। समय शाम साढ़े पांच बजे से है।

अब 2031 नहीं 2047 की आबादी के आधार पर तैयार होगा भोपाल का मास्टर प्लान

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल के जिस मास्टर प्लान 2031 पर दावे-आपत्तियां सुनी गई थीं, उसे अब बार फिर नए सिरे से तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। नया मास्टर प्लान वर्ष 2047 तक होने वाली संभावित आबादी के अनुपात में जरूरतों ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को लेकर शुक्रवार को शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जनप्रतिनिधियों ने पुराने मास्टर प्लान के कई प्रविधानों पर असहमति जताई और भविष्य के लिए सुझाव दिए। विजयवर्गीय ने नए बिंदुओं और मिले सुझावों के आधार पर नया मास्टर प्लान बनाने की बात कही।नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भोपाल के सभी तालाब विशेष रूप से बड़ा तालाब यहां की लाइफ लाइन और पर्यटकों के

लिए विशेष आकर्षण है। तालाब और भोपाल की पुरातत्वीय विरासत को संरक्षित करते हुए मास्टर प्लान में प्रविधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि, भोपाल का पृथक से ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें सड़कों की पर्याप्त चौड़ाई, फ्लायओवर और मेट्रो सेवा के साथ-साथ विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राजधानी के सुव्यवस्थित विकास और नागरिकों को सभी बुनियादी सुविधाएं सुलभ तरीके से मिल सके, इसके लिये सभी प्रविधान किए जाएंगे। बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर, महापौर मालती राय, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक रामेश्वर शर्मा, आतिफ अकील, पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह, पूर्व निगम अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा और प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई भी मौजूद थे। मास्टर प्लान 2031 के इन बिदुओं पर आपत्ति - शहरी क्षेत्र के साथ 32 पंचायतों को भी शामिल किया जाने पर विधायक रामेश्वर शर्मा पहले ही आपत्ति जता चुके हैं, उनका कहना है, इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति नहीं ली गई। - बड़े तालाब का कैचमेंट क्षेत्र बिना किसी मुआवजे एवं नोटिफिकेशन के 2800 हेक्टेयर से 3872 हेक्टर करने पर तालाब के नजदीक के गांवों के किसान लगातार आपत्ति ले रहे हैं। - हरियाली वाले क्षेत्र को विकास क्षेत्र में सम्मलित करने पर जागरुक नागरिकों ने की आपत्ति। - एक हजार वर्गफीट तक के भूंखडों पर एमओएफ पर छूट का प्रविधान नहीं होने पर हैं कई आपत्तियां। मास्टर प्लान को लेकर लिए गए निर्णय के प्रमुख बिंदु - भोपाल मास्टर प्लान का नये सिरे से ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। - संपूर्ण प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक पूरी की जायेगी। -पूर्व के मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में प्राप्त करीब पांच हजार से अधिक आपत्तियों को ध्यान में रखकर नवीन ड्राफ्ट मई-2024 में प्रकाशित किया जाएगा। - 30 प्रतिशत कंपाउंडिंग नगद भुगतान पर करने के लिये अगस्त-2024 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। - नवीन मास्टर प्लान अब वर्ष 2031 के स्थान पर वर्ष 2047 तक की आवश्यकताओं के आधार पर बनाया जाएगा।

संपादकीय

रूस-यूक्रेन युद्ध और नाटो की पहेली....

आज यानी शनिवार 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले को दो वर्ष पूरे हो रहे हैं। लेकिन कीव (यूक्रेन की राजधानी), मॉस्को और ब्रसेल्स (यूरोपीय संघ और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का मुख्यालय) में सबकी नजरें नवंबर में होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों पर लगी हुई हैं। इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डॉनल्ड ट्रंप का नामांकन तय माना जा रहा है और उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने की काफी अधिक संभावना है। यूरोपीय संघ और यूक्रेन के लिए ट्रंप की जीत से बुरा शायद ही कुछ घटित हो। यह बात 10 फरवरी को उस समय साबित हुई जब उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिका नाटो के ऐसे सदस्य देश का बचाव नहीं करेगा जो अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का दो फीसदी से भी कम हिस्सा रक्षा पर खर्च करता हो। इसके उलट उन्होंने जोर देकर कहा कि वह रूस से कहेंगे कि वह जो करना चाहता है करे। यह वक्तव्य पिछले दिनों म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में छाया रहा और यह 75 साल पुराने इस समझौते के अनुच्छेद पांच का उल्लंघन करता है जिसमें कहा गया है कि नाटो के किसी सदस्य देश पर हमले को सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। यह यूक्रेन के लिए जाहिर तौर पर बुरी खबर है क्योंकि वह पहले ही रक्षा उपकरणों की कमी से जूझ रहा है। उधर अमेरिकी कांग्रेस के रिपब्लिकन बहुल निम्न सदन में यूक्रेन को सैन्य और नागरिक सहायता देने का विरोध किया जा रहा है। यूक्रेन नाटो का पूर्ण सदस्य नहीं है लेकिन वह उसके दशक भर पुराने एक कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका अर्थ यह है कि वह नाटो के साथ करीबी सहयोग करता है। यूक्रेन को लगने वाला सैन्य झटका यूरोप की सुरक्षा के लिए भी खतरा होगा। नाटो के सदस्यों द्वारा अपेक्षा से कम व्यय ने भी ट्रंप और उनके पहले के राष्ट्रपतियों को नाराज किया था। हालांकि उनकी नई धमकी में इस तथ्य की अनदेखी की गई है कि दो फीसदी निवेश का निर्देश बाध्यकारी नहीं है। सबसे पहले 2006 में नाटो के रक्षा मंत्रियों ने यह वादा इसलिए किया था कि इससे बोझ को वहन करने में आसानी होगी। जब रूस ने 2014 में क्राइमिया का अधिग्रहण कर लिया तो इस बात को दोहराया गया। ट्रंप प्रशासन का यह कहना सही था कि अधिकांश नाटो सदस्य इस प्रतिबद्धता की अनदेखी करते हैं। वर्ष 2014 में केवल तीन सदस्य देशों ने अपने जीडीपी का दो फीसदी रक्षा पर खर्च किया था। उसके बाद से हालात में बदलाव आया है क्योंकि यूरोप को डर है कि रूस कभी भी आक्रमण कर सकता है। इस वर्ष नाटो के 31 में से 18 सदस्य देशों के इस लक्ष्य को हासिल करने की अपेक्षा है। बाल्टिक देश जो रूसी आक्रमण की स्थिति में सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में सामने आएंगे, उन्होंने अपनी पूर्वी सीमा को सुदृढ़ करने का काम आरंभ कर दिया है। पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ही क्षेत्रों में यूरोप और रूस में जो असमानता है उसे देखते हुए यह स्पष्ट नहीं है कि नाटो बिना अमेरिकी सैन्य मदद के प्रभावी बचाव कैसे कर पाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि यूरोप को अधिक व्यय करना होगा। भारत के लिए सवाल यह है कि उसे अमेरिका के अलावा नाटो को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यह समूह विश्व युद्ध के बाद के सुरक्षा ढांचे में अहम रहा है। यह बात ध्यान देने वाली है कि गत वर्ष जून में भारत ने अमेरिका की उन भावनाओं को नकार दिया था जिनमें वह चाहता था कि भारत चीन पर केंद्रित नाटो प्लस में शामिल हो। इस समूह में नाटो के अलावा अमेरिका के पांच सहयोगी देश- ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजरायल और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। यह अनौपचारिक समूह चीन के साथ क्षेत्रीय तनाव की स्थिति में सुरक्षा मुहैया करा सकता है। विदेश मंत्री का कहना था कि इसमें शामिल होने से देश की सामरिक स्वायत्तता सीमित हो जाएगी। खासतौर पर यह देखते हुए कि भारत शांघाई सहयोग संगठन का भागीदार है। भारत का कूटनयिक संतुलन उसे अच्छी स्थिति में रखे हुए है। अटलांटिक पार के संबंधों में किसी भी तरह के बदलाव में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

चुनावी बॉन्ड योजना : क्या अब पार्दर्शिता आएगी राजनीतिक फंडिंग पर बाकी हैं कुछ आशंकाएं

इस मामले में याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह थी कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और कंपनी अधिनियम के तहत राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता के उद्देश्य को विफल करती है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था के अभाव में चुनावी बॉन्ड योजना के खत्म हो जाने पर पारदर्शिता आने के बजाय राजनीतिक फंडिंग के और अधिक अपारदर्शी हो जाने की आशंका है।सर्वोच्च न्यायालय ने वित्त अधिनियम, 2017 में पेश की गई चुनावी बॉन्ड योजना को हाल ही में रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। अदालत ने यह भी माना कि असीमित कॉरपोरेट फंडिंग की अनुमति देने वाली कंपनी अधिनियम की धारा 182(1) के प्रावधान को हटाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत पेश करता है। शीर्ष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से कहा है कि 12 अप्रैल, 2019 तक की गई ऐसी सभी खरीद का विवरण आगामी छह मार्च तक चुनाव आयोग को दें। साथ ही चुनाव आयोग को एसबीआई से मिली सभी जानकारियों को अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च तक प्रकाशित करना होगा। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत कोई व्यक्ति या संगठन उन्हें खरीद सकता है और अपनी पसंद के राजनीतिक दल को दान कर सकता है। ये दल उन्हें 15 दिन के बाद भुना सकते हैं। इन बॉन्डों को खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए सख्त केवाईसी मानदंड हैं। खरीदारों की पहचान एसबीआई को होती है, जिसके पास इसके लेन-देन का एक समर्पित विंग है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह थी कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और कंपनी अधिनियम के तहत राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता के उद्देश्य को विफल करती है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था के अभाव में चुनावी बॉन्ड योजना के खत्म हो जाने पर पारदर्शिता आने के बजाय राजनीतिक फंडिंग के और अधिक अपारदर्शी हो जाने की आशंका है। दरअसल, कोई भी कंपनी किसी राजनीतिक दल को बड़ा चंदा नहीं देना चाहेगी, और विशेष रूप से खुलेआम ऐसा करते हुए दिखना भी नहीं चाहेगी। इसकी वजह यह नहीं है कि कॉरपोरेट फंडिंग किसी भी तरह से भ्रष्ट या अवैध है, बल्कि यह है कि कोई खास व्यक्ति या कंपनी किसी खास राजनीतिक दल को इसलिए पसंद करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आर्थिक नीतियां एवं विचार अन्य दलों से बेहतर हैं। लेकिन इस व्याख्या को या तो अस्वीकार्य माना जाता है या छोड़ दिया जाता है। स्वतंत्र भारत का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है कि पहले इस तरह के राजनीतिक चंदे गुप्त रूप से या अधिकांशतः भ्रष्ट तरीके से दिए जाते थे। चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक चंदे के उन अनियमित साधनों को खत्म करने के लिए एक सुधारात्मक योजना थी। बॉन्ड नकद नहीं खरीदे जा सकते थे और उनकी खरीद के लिए सख्त केवाईसी मानदंडों की आवश्यकता थी। यह एक मिथक है कि भारतीय लोकतंत्र छोटे दान से जीवित रह सकता है और बड़े पैमाने पर राजनीतिक अभियान जारी रख सकता है, जो भारतीय राजनीति की विशेषता है। अब समय आ गया है कि भारत को आधुनिक एथेंस के रूप में देखना बंद कर दिया जाए, जहां छोटी-मोटी नकदी और अल्पकालिक चंदा पारदर्शिता के लिए अद्भुत काम करेगी। चुनाव प्रचार में खर्च होने वाली राशि पर विचार करें। वर्ष 2019 के चुनाव में 55 से 60 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इतनी ज्यादा रकम चुनावों की स्टेट फंडिंग से नहीं आ सकती। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यह पैसा दान से भी नहीं आ सकता है। यह विश्वास कि चुनाव को परोपकारी संरक्षकों द्वारा वित्तपोषित किया जा सकता है, शहरी आख्यान है। भारतीय लोकतंत्र खर्चीला है, लेकिन भारतीय राजनीति को पवित्र करने की इच्छा रखने वाले एक्टिविस्ट वकील इस तथ्य को स्वीकार करने से इन्कार करते हैं। कागज पर अदालत का फैसला 'सूचनात्मक लोकतंत्र' की धारणा को आगे बढ़ाता है, जहां मतदाता राजनीतिक दलों, संबंधित उम्मीदवारों और इन पार्टियों और उम्मीदवारों की नीतियों के बारे में जानकारी के आधार पर विकल्प चुनते हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा, 'प्रभावी ढंग से अपनी पसंद के उम्मीदवार को मतदान करने के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है।' लेकिन सर्वोच्च अदालत के फैसले से यही लगता है कि न्याय एक बार फिर मुट्ठी भर एक्टिविस्ट वकीलों द्वारा फैलाए गए राजनीतिक जाल में फंस गया है। सवाल यह है कि ऐसी बेहतर जानकारी की उपलब्धता मतदाता की पसंद को किस हद तक प्रभावित करेगी? शहरी क्षेत्रों के एक बेहद छोटे वर्ग को छोड़कर भारत के अधिकांश लोग राजनीतिक फंडिंग के स्रोतों की परवाह नहीं करते। ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण भारत में फसलों के लाभकारी मूल्य, खाद-बीज की कीमत, सरकारी नौकरी, शिक्षा के अवसर और जीवन की संभावनाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। कुछ अत्यंत भ्रष्ट पार्टियां और राजनेता ये सब चीजें उपलब्ध कराकर सफल हो जाते हैं, जबकि अच्छे उम्मीदवार और पार्टियां विधानसभाओं में प्रवेश नहीं पातीं, क्योंकि वे वह नहीं कर पाते, जो भारतीय राजनीति की उथल-पुथल में आवश्यक है। इसकी संभावना बहुत कम है कि राजनीतिक दलों के फंडिंग स्रोतों का पता चलने से मतदाताओं के बेहतर चुनावी विकल्प चुनने पर कोई प्रभाव पड़ेगा। यह एक और शहरी कानूनी किंवदंती है। अब जबकि लोकसभा के चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि चुनावी फंडिंग के मोर्चे पर आगे क्या होगा। लेकिन यह साफ है कि जैसे पानी अपने बहने का रास्ता ढूंढ लेता है, राजनीतिक दल भी फंडिंग का रास्ता ढूंढ लेंगे। कई लोगों को इस बात से परेशानी थी कि चुनावी बॉन्ड योजना के तहत दान का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की झोली में चला गया। कथित तौर पर यह अन्य राजनीतिक दलों से समान अवसर छीन लेता था। यह उन लोगों की वास्तविक, लेकिन अघोषित शिकायत के मूल में था, जो चुनावी बॉन्ड योजना को गैर-कानूनी घोषित करना चाहते थे। यह याद रखने योग्य है कि भारतीय राजनीति की प्रकृति ऐसी है कि सत्तारूढ़ पार्टी ही राजनीतिक अभियानों के लिए जरूरी अधिकतम संसाधन जुटाती है। यह जवाहर लाल नेहरू के भारत के लिए भी उतना ही सच था, जितना आज है। लेकिन प्रचार की ताकत ऐसी है कि इतिहास के इस पहलू को या तो नकार दिया जाता है या दबा दिया जाता है और अतीत को सुनहरे रंगों में रंग दिया जाता है, जबकि समकालीन वास्तविकता को अंधकारमय बताया जाता है।

विश्व सिनेमा की जादुई दुनिया
आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख तिब्बत सिनेमा

तिब्बत के फिल्म निर्माताओं को राजनैतिक तथा सामाजिक दृष्टि से खासतौर पर सावधान रहना पड़ता है, फिर भी तिब्बत के लोग, जिसमें प्रवासी तिब्बती शामिल हैं, फिल्म बना रहे हैं। चीन अधिकृत तिब्बत में रहते हुए पेमा सिडेन तथा सोंथर गियाल फिल्में बना रहे हैं।हमारा पड़ोसी देश तिब्बत भी सिनेमा बनाता है, यह बात कई लोगों के लिए आश्चर्यचकित करने वाली है। यह सत्य है, तिब्बत में फिल्में बनती हैं और दूसरे देशों में रहने वाले तिब्बत के लोग भी फिल्म बनाते हैं। तिब्बती भाषा में भी फिल्में बनती हैं। ये फिल्में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित होती हैं। हां, इनका विषय आम फिल्मों से तनिक हट कर होता है। चीन के जबरदस्ती अधिकृत करने के बाद तिब्बत के लोग, खासकर बौद्धिक लोग तिब्बत छोड़ने को बाध्य हुए। इनमें से कलाकार प्रवृति के कुछ लोगों की रुचि सिनेमा में थी। ये तिब्बत से बाहर रहते हुए, तिब्बत पर आंख रखते हुए फिल्म बनाने की दिशा में सक्रिय रहे। ये अपनी सभ्यता-संस्कृति से जुड़े लोग हैं। तिब्बत की राजनैतिक तथा भौगोलिक चुनौतियों का समाना करते हुए फिल्म बना रहे हैं और अपनी संस्कृति का अन्वेषण कर रहे हैं। संगीतज्ञ, पेंटर, लेखक अपना काम स्वयं कर सकते हैं, उन्हें अपने कार्य के प्रसार-प्रचार के लिए दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है। फिल्म बनाने हेतु प्रारंभ से दूसरों की जरूरत होती है। फिल्म बनाना एक टीम वर्क है। इसके बनाने में बहुत खर्च आता है, अतः फाइनेंसर चाहिए होता है, फोटोग्राफर, एडीटर, डिस्ट्रिब्यूटर आदि की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है फिल्म को एक जटिल नेटवर्क चाहिए होता है।फिल्म को लेकर चीन का प्रशासन बहुत सख्त है, चीन में बनी फिल्मों पर भी सेंसरशिप की तलवार लटकती रहती है। तिब्बत उसका बहुत संवेदनशील इलाका है इसलिए स्वायत्त तिब्बत इलाके में बनने वाली फिल्मों के लिए चीनी प्रशासन के नियम और अधिक कठोर हैं। उन्हें विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। तिब्बत के फिल्म निर्देशकों केलिए यह एक बड़ी चुनौती है। तिब्बत के फिल्म निर्माताओं को राजनैतिक तथा सामाजिक दृष्टि से खासतौर पर सावधान रहना पड़ता है, फिर भी तिब्बत के लोग, जिसमें प्रवासी तिब्बती शामिल हैं, फिल्म बना रहे हैं। चीन अधिकृत तिब्बत में रहते हुए पेमा सिडेन तथा सोंथर गियाल फिल्में बना रहे हैं। सोंथर गियाल फिल्म निर्देशक तथा सिनेमाटोग्राफर हैं। अपनी पहली फिल्म 'द सन बीटेन पाथ' का लेखन एवं संपादन भी उन्होंने स्वयं किया है। उनकी यह रोड मूवी तिब्बत के मिथक को न दिखाते हुए हिमालय के इस भू-भाग की सपाट, वनस्पति विहीन प्रकृति को कैमरे से बखूबी पकड़ती है। फिल्म में एक युवा नीमा (येशे हार्दुक) बहुत परेशान है और पश्चाताप मुक्ति केलिए वह यात्रा पर जाते हुए एक वृद्ध (लो ची) से मिलता है। मगर वृद्ध का दोस्ती केलिए बढ़ा हाथ वह ठुकरा देता है।मगर इसके बहुत पहले 1957 तथा 1997 में एक ही शीर्षक से दो फिल्में बनीं। इनका नाम है, 'सेवेन ईयर्स इन तिब्बत'। 1957 की फिल्म हैन्स निएटर ने बनाई थी। इस सवा घंटे की फिल्म में एक ऑस्ट्रियन पर्वतारोही हैनरिच हैरेर जाता तो हिमालय चढ़ने है मगर युद्ध बंदी बन जाता है। किसी तरह वह वहां से छूट निकलता है और तिब्बत के 14वें दलाई लामा से दोस्ती करता है। फिल्म में स्वयं हैनरिच हैरेर तथा दलाई लामा ने भूमिकाएं की हैं।1997 की 'सेवेन ईयर्स इन तिब्बत' को जीन जेकब एनौड ने निर्देशित किया है और इस बायोपिक का लेखन स्वयं हैनरिच हैरेर ने बेकी जॉनसन के साथ मिल कर किया है। तीन पुरस्कार जीतने वाली इस फिल्म में हैनरिच हैरेर की भूमिका प्रसिद्ध अभिनेता बैड पिट ने की है। अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर जब यह पर्वतारोही तिब्बत में है तभी चीन तिब्बत को हथियाता है। आया तो यह जुनूनी पर्वत चढ़ने है मगर फंस जाता है तिब्बत की हलचल भरी राजनीति में। वह युद्ध बंदी हो जाता है और वहां से किसी तरह निकलता है। इस फिल्म में पहली फिल्म से कई घटनाएं भिन्न हैं, शायद इसीलिए इसकी लंबाई (सवा दो घंटे) भी अधिक है। चीन के दमन को यहां दिखाया गया है।

पूर्णिमा पर त्रिपुंड, चंद्र और त्रिशूल से किया बाबा महाकाल का श्रृंगार, गर्भग्रह में फूलों से सजावट

उत्तरप्रदेश गाजियाबाद से आए राहुल सोनी और दीपिका वर्मा ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में रजत का पांच मंजिल झूमर (छत्र) भगवान महाकाल को अर्पित किया गयाविश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर शनिवार तड़के भस्म आरती के दौरान चार बजे मंदिर के पट खुलते ही पंडे पुजारी ने गर्भगृह मे स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन किया। दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर पूजन किया गया। प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को रजत का मुकुट, त्रिपुंड, चन्द्र और त्रिशूल धारण करवाया गया। आज के श्रृंगार की विशेष बात यह रही कि आज बाबा महाकाल का श्रृंगार किए जाने के साथ ही गर्भग्रह में भी फूलों से आकर्षक सजावट की गई। श्रृंगार के बाद बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग को कपड़े से ढांककर भस्म रमाई गई। इसके बाद महाकाल को रजत की मुण्डमाल और रुद्राक्ष की माला के साथ सुगंधित पुष्पों की माला अर्पित कर फल और मिष्ठान का भोग लगाया गया।

स्वस्थ लोकतंत्र और सुशासन के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग जरूरी

जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 2 मार्च 2023 को कुछ याचिकाओं पर फैसला दिया था कि अब राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग के मुख्य न्यायाधीश समेत आयुक्तों की नियुक्ति एक कमटी की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिपक्ष या लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता और स्पीकर शामिल होंगे।ठीक 18वीं लोकसभा के चुनाव से पहले भारत निर्वाचन अयोग की निष्पक्षता फिर चर्चा में आ गई है। चर्चा का विषय निर्वाचन आयुक्तों के चयन से शुरू हो कर अब चुनावी बॉड पर टिक गया है। केन्द्र सरकार ने चुनाव सुधार की प्रकृया में जिस चुनावी बॉंड व्यवस्था को शुरू किया था उसे सर्वोच्च न्यायलय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इससे पहले मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायलय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता एक चयन समिति के गठन का अदेश पारित किया था जिसमें प्रधान न्यायाधीश के प्रतिनिधि समेत लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में प्रतिपक्ष या सबसे बड़े दल नेता ने शामिल होना था। अदालती आदेश के क्रम में चयन समिति का कानून सरकार ने संसद से पास करा लिया है जिसमें प्रधान न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केन्द्रीय मंत्री को सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है।जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायलय की संविधान पीठ ने 2 मार्च 2023 को कुछ याचिकाओं पर फैसला दिया था कि अब राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग के मुख्य न्यायाधीश समेत आयुक्तों की नियुक्ति एक कमटी की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिपक्ष या लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता और स्पीकर शामिल होंगे। आदालत का यह आदेश इस दिशा में नया कानून पास होने तक लागू रहना था, क्योंकि कानून बनाने का दायित्व अदालत का नहीं बल्कि संसद का है। इस दिशा में केन्द्र सरकार ने संसद से नया कानून पास करा दिया है। अब संसद द्वारा पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 की धारा 7 में प्रावधान किया गया है कि ''मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। समिति में (ए) प्रधान मंत्री - अध्यक्ष (बी) लोक सभा में विपक्ष के नेता - सदस्य (सी) प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री - सदस्य होंगे। हालांकि इस कानून को चुनौती देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग एडीआर नाम के एनजीओ ने सर्वोच्च न्यायालय से की थी जिस अदालत ने खरिज कर दिया लेकिन याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होनी है। चुनाव सुधारों की प्रक्रिया 1951 से ही शुरू हो गई थी। इसी क्रम में आयोग को निष्पक्ष बनाने एवं चुनाव में धनबल, बाहुबल जैसे अनुचित माध्यमों का इस्तेमाल रोकने के लिए 1974 में तारकुण्डे समिति से लेकर 2010 में तनखा समिति तक 8 के करीब समितियों का गठन हो चुका है। सभी ने निर्वाचन प्रक्रिया में शुचिता के लिए कई सुझाव दिए जिन पर कार्यवाही भी हुई। जैसे इलेक्शन पीटीसन के लिए ट्रिब्यूनल में जाने के बजाय हाइकोर्ट में जाना, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना, ईवीएम मशीनों का प्रयोग, मतदाता पहचान-पत्रों का चलन, दो से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर रोक, मतदान कर्मियों को सीधे निर्वाचन आयोग के अधीन करना, चुनाव खर्च की सीमा तय करना और मतदान समाप्त होने से आधे घण्टे पहले तक एक्जिट पोल पर रोक आदि शामिल हैं। पहले एक सदस्यीय आयोग होता था। अब दो अन्य आयुक्त भी आयोग में शामिल कर लिए गए हैं। लेकिन आयोग में सुधार के लिए जो सिफारिशें की गई थीं उन पर कार्यवाही नहीं हुई। आयोग में दो अतिरिक्त आयुक्तों की पहली बार नियुक्ति 16 अक्टूबर 1989 को हुई थी जिनका कार्यकाल बहुत ही कम 1 जनवरी 1990 तक रहा। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 से नियमित रूप से केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य आयुक्त के साथ दो अन्य आयुक्त नियुक्त किए जाने लगे।तारकुंडे समिति (1974-75) के बाद दिनेश गोस्वामी समिति (1990) ने भी निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष और दबाव मुक्त बनाने के लिए आयोग की नियुक्तियों में सरकार का एकाधिकार समाप्त करने की सिफारिश की थी। तारकुंडे समिति की सिफारिश पर मतदान की उम्र 21 से घटा कर 18 तो हो गई मगर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार केन्द्र सरकार ने नहीं छोड़ा। तारकुंडे समिति ने तीन सदस्यीयएक कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष का नेता या विरोध पक्ष का प्रतिनिधि होना था। तारकुण्डे समिति ने निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए केंद्र और राज्यों में स्वायत्त निर्वाचन परिषदें बनाने का भी सुझाव दिया था। इससे साथ ही अनुचित कामों पर निगरानी के लिये ''मतदाता परिषद'' के गठन का भी सुझाव दिया था।मई 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने भी निर्वाचन आयोग तीन सदस्यीय निकाय बनाने का सुझाव दिया था। समिति की सिफारिश थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता द्वारा की जानी चाहिए और अन्य सदस्यों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त से विचार-विमर्श करके की जानी चाहिए। समिति ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक करने की सिफारिश भी की थी। उसके बाद सरकारों ने अन्य सिफारिशें तो मान लीं मगर निर्वाचन आयोग पर सरकारी नियंत्रण हटाने की सिफारिश अब तक की सभी सरकारें टाल गईं। वर्तमान में मुख्य निर्चाचन आयुक्त को सरकार अपनी सुविधानुसार नियुक्त करती है और उसे केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है और संसद में सत्ताधारी दल का ही बहुमत होता है। अब तक निर्वाचन आयोग से लेकर सीएजी और लोकसेवा आयोगों में लगभग सभी संवैधानिक पदों पर केन्द्र सरकार अपने पसंद के लोगों को नियुक्त करती रही है। सवाल उठता है कि जब सीबीआई निदेशक, सूचना आयुक्त और लोकपाल/लोकायुक्त जैसे संवैधानिक पदों पर सरकार, न्यायपालिका, विधायिका और प्रतिपक्ष के नेता वाली कमेटी की सिफारिश पर नियुक्तियां हो सकती हैं तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां भी इसी तरह सर्व सर्वम्मति से क्यों नहीं हो सकतीं?

सिंगल कॉलम

आमिर को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनाने में बिग बी का बड़ा हाथ, अभिनेता ने बताया यह दिलचस्प किस्सा

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान अपने किरदार को परफेक्ट बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। वे अपने रोल को लेकर छोटी सी छोटी चीजों का भी खास ध्यान रखते हैं, इसलिए, उन्हें बॉलीवुड का मि. परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। अपने हर शॉट को परफेक्ट बनाने के लिए आमिर अपने डायलॉग का घंटो अभ्यास करते हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार आमिर ने खुलासा किया कि उनकी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक के दौरान अमिताभ बचन ने उन पर खास प्रभाव छोड़ा था, जिन्होंने उन्हें अपने किरदार पर फोक्स रखना सिखाया। साक्षात्कार में अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म लापता लेडीज के प्रमोशन के दौरान आमिर खान ने इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं अपनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक की शूटिंग कर रहा था। मेरे मेकअप रूम के थोड़ी दूरी पर ही एक और फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जहां एक बड़े अभिनेता करीब 100 से 200 बार अपने डायलॉग का रिहर्सल कर रहे थे और वे कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बचन थे।आमिर खान ने बताया कि जब उन्होंने ये देखा तो हैरान रह गए। आमिर ने आगे कहा, अमित जी जैसे सुपरस्टार को ऐसे रिहर्सल करते देख मै हैरान रह गया था। उन्हें इतनी मेहनत करते हुए देख मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस दौरान अमित जी को एक लंबे दृश्य की शूटिंग करनी थी। उन्होंने 8 से 10 टेक दिए और शॉट खत्म होने के बाद वे निर्देशक प्रकाश मेहरा के पास गए। इसके बाद उन्होंने निर्देशक से कहा प्रकाश, मैं बहुत तेजी से तो नहीं बोल रहा था।

महाराष्ट्र भूषण सम्मान मिलने पर अशोक सराफ ने व्यक्त की अपनी भावनाएं

मुंबई लोकप्रिय और दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ को मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मुंबई के वर्ली में आयोजित 57वें राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। महाराष्ट्र भूषण सम्मान पाने के बाद अशोक सराफ ने मंच पर भावनाएं व्यक्त कीं।

महाराष्ट्र भूषण अशोक सराफ ने कहा, 'मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसकर, मनीषा कायंदे को सलाम करता हूं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि आपने मुझे आज महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और नंबर वन पुरस्कार दिया है। महाराष्ट्र, जहां मेरा जन्म हुआ, जो मेरी मातृभूमि है, इससे बड़ी कोई बात नहीं कि आज यहां मेरा अभिनंदन किया जाए। मैं इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को दिल से सलाम करता हूं। क्योंकि पहले भी यह पुरस्कार प्राप्त कर चुके लोगों की सूची इतनी लंबी है कि मैं इसमें शामिल होना कभी नहीं भूलूंगा।'

फिल्म उद्योग में अपनी यात्रा के बारे में बात करते हुए अशोक सराफ ने कहा, 'अगर हम समग्र रूप से मेरी यात्रा के बारे में बात करते हैं तो यह लगभग 50 वर्षों का करियर है। अब तो मुझे सबकुछ याद भी नहीं। लेकिन, जिन लोगों ने इस पूरे सफर में मेरी मदद की। चाहे वह निर्देशक हों या मेरे साथ काम करने वाले छोटे कर्मचारी, तकनीशियन, उन सभी ने बिना जाने ही हमेशा मेरी मदद की है। यदि उनका निरंतर सहयोग न मिला होता तो मैं आज इस पद पर न पहुँच पाता। आखिरकार आप मेरे दर्शक हैं। आप दर्शकों के सामने कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। हमें प्रदर्शन करते समय हमेशा हर चीज के प्रति सचेत रहना होगा। 'एक कलाकार के लिए दर्शक ही सबसे बड़े होते हैं। आप तारीफ करने नहीं आओगे तो हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता कि मैं आपके उपकार का बदला कब चुकाऊंगा। मैं आपका एहसान चुका भी नहीं पाऊंगा। आपके प्रति मेरा प्यार हमेशा बना रहेगा। मुझे इतना सम्मान देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।' यह बात अशोक सराफ ने व्यक्त की।

आर्टिकल 370 की अच्छी शुरुआत, क्रैक नहीं दिखा सकी कमाल, जानें अन्य फिल्मों का हाल

फरवरी के महीने में कई मशहूर सितारों की फिल्में सिनेमाघरों में लोगों के मनोरंजन के लिए प्रदर्शित हो रही हैं। इनमें शाहिद कपूर की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ऋतिक की फाइटर और हाल ही में रिलीज हुई विद्युत जामवाल की क्रैक और यामी गौतम की आर्टिकल 370 फिल्म शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि किन फिल्मों ने इस शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की... विद्युत जामवाल, नोरा फतेही और अर्जुन रामपाल अभिनती फिल्म क्रैक ने इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर धीमी हुई है। पहले दिन इस फिल्म ने महज चार करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस फिल्म का बजट 60 करोड़ के आस पास है। ऐसे में इसे हिट होने के लिए आने वाले दिनों में अच्छी कमाई करनी होगी।

कंगना ने फिल्मी हस्तियों पर लगाया बड़ा आरोप

बोलीं- कार्रवाई हो, तो कई नाम होंगे उजागर

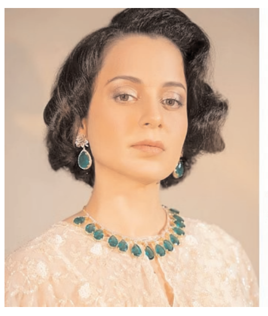

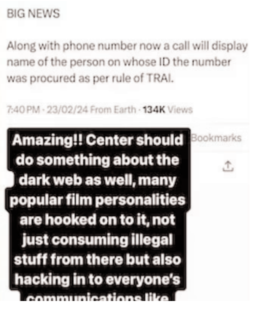

अभिनेत्री कंगना रणौत अपनी अदाकारी के साथ-साथ अपने बातों को बेबाकी से रखने के लिए भी जानी जाती हैं। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक तस्वीर साझा की है। तस्वीर साझा कर अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि लोकप्रिय फिल्मी हस्तियां व्हाट्सएप जैसे लोगों के संचार ऐप को हैक करने के लिए डार्क वेब का उपयोग करती हैं।

डार्क वेब पर भी हो कार्रवाई

कंगना ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया। पोस्ट में उन्होंने बताया कि कैसे फोन नंबरों के साथ-साथ लोगों के पंजीकृत नाम, जिनके तहत उन नंबरों को खरीदा गया है। उनको फोन कॉल करते समय सब स्क्रीन पर दिखेगा। उन्होंने सरकार के इस की सराहना की और लिखा, यह बहुत अछा काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र को डार्क वेब के बारे में भी कुछ करना चाहिए। बॉलीवुड सितारों को लेकर कही यह बात उन्होंने आगे कहा, बॉलीवुड की कई मशहूर सितारे इसकी आदी हो गई हैं, न केवल वहां से अवैध सामान ले रही है, बल्कि व्हाट्सएप और मेल जैसे सभी के संचार को भी हैक कर रही हैं। अगर वे उन पर कार्रवाई करेंगे, तो कई बड़े नाम उजागर होंगे। बता दें कि बीते दिनों अभिनेत्री ने अभिनेता अक्षय कुमार की पत्नी और अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना को आड़े हाथ लिया था। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ट्विंकल का एक वीडियो साझा कर ट्विंकल को खरी खोटी सुनाई थी। वीडियो में अभिनेत्री पुरुषों की तुलना पॉलीथीन बैग से करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसे लेकर कंगना ने उन्हें नेपो किड कहा था।

जैकी भगनानी-रकुल प्रीत की शादी की तस्वीरें खूब हो रही वायरल

मुंबई पिछले साल से ही बॉलीवुड में शादियों की धूम है। एक के बाद एक एक्टर शादी के बंधन में बंध रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी आइरा खान जनवरी के पहले हफ्ते में बॉयफ्रेंड नुपुर शिखर के साथ शादी के बंधन में बंध गईं। इसके बाद अब एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और एक्टर जैकी भगनानी शादी के बंधन में बंध गए हैं। उनकी शादी की पहली फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।रकुल और जैकी पिछले कुछ सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर डिनर डेट और सैर पर जाते देखा जाता था। अब उन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने का फैसला कर लिया है। दोनों की शादी का समारोह बड़ी धूमधाम से किया गया है। उनकी शादी की पहली फोटो सामने आ गई है।फोटो में रकुल ने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ है। साथ ही सफेद हीरे की ज्वेलरी भी पहनी हुई है। इस ब्राइडल लुक में रकुल बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लग रही हैं। वहीं जैकी ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी हुई है। इस पर एक खूबसूरत हीरे का हार रखा हुआ है। इस लुक में जैकी बेहद हैंडसम लग रहे हैं। दोनों का वेडिंग लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा है। सोशल मीडिया पर जैकी और रकुल की तस्वीरों पर फैंस ने लाइक्स की बौछार कर दी है। कलाकारों ने कमेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। रकुल और जैकी की शादी का समारोह बेहद निजी तरीके से आयोजित किया गया है। उनकी शादी का समारोह गोवा में कुछ लोगों की मौजूदगी में हुआ। उनकी शादी की रस्मों में सिंधी और पंजाबी दोनों रीति-रिवाज निभाए गए।

शादी में शामिल हुए अभिनेता रकुल और जैकी ने शादी में मुट्ठी भर परिवार और दोस्तों को आमंत्रित किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे, वरुण धवन, शाहिद कपूर, मीरा कपूर, आदित्य रॉय कपूर, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा मौजूद रहे। कहा जाता है कि शिल्पा शेट्टी ने शादी में डांस किया।

ये हैं तमिल सिनेमा के सबसे अमीर अभिनेता, संपत्ति जानकर उड़ जाएंगे होश

डेस्क। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने बीते कुछ वर्षों में हैरतअंगेज तरीके से पूरे देश में जबर्दस्त लोकप्रियता हासिल की है। साउथ के सितारों की फैन फॉलोइंग अब केवल अपने राज्यों तक ही सीमित नहीं है। देश के हर कोने से उन्हें बेशुमार प्यार मिल रहा है। ऐसे में आज हम आपको तमिल सिनेमा के उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, प्रतिभा के जरिए से भारी संपत्ति अर्जित की है।

कमल हासन : सबसे अमीर तमिल अभिनेता में पहले स्थान पर कमल हासन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 450 करोड़ रुपये है। अपने फिल्मी करियर में वे अब तक 230 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनमें तमिल के अलावा मलयालम, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली भाषा की फिल्में भी शामिल हैं।

विजय :तमिल सुपरस्टार विजय संपत्ति के मामले में कमल हासन के ज्यादा पीछे नहीं हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी कुल संपत्ति 445 करोड़ रुपये है। हाल ही में उनकी फिल्म लियो ने बॉक्स ऑफिस पर जबर्दस्त कमाई की थी। लोकेश कनगराज की इस फिल्म के लिए उन्होंने कथित तौर पर 120 करोड़ रुपये की फीस ली थी।

रजनीकांत :इस लिस्ट में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक रजनीकांत का नाम भी शामिल है। वे कथित तौर पर कुल 430 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी जेलर के लिए उन्होंने 210 करोड़ रुपये (पारिश्रमिक के रूप में 110 करोड़ रुपये और लाभ के आधार पर 100 करोड़ रुपये) की फीस ली थी।

अजित कुमार : अजित कुमार भी तमिल सिनेमा के सबसे अमीर सितारों में से हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता की कुल संपत्ति 350 करोड़ रुपये है। उन्हें बड़े पर्दे पर आखिरी बार एच. विनोथ की थुनिवु में देखा गया था, जिसके लिए उन्होंने कथित तौर पर 70 करोड़ रुपये लिए थे। उनकी आगामी फिल्म की बात करें तो वे जल्द ही मगिज थिरुमेनी की विदा मुयार्ची में दिखाई देंगे।

पति की तुलना प्लास्टिक बैग से करने पर ट्विंकल पर भड़कीं कंगना

मुंबई। कंगना रनौत लगातार सोशल मीडिया पर अलग-अलग पोस्ट के जरिए चर्चा में बनी हुई हैं। कंगना सोशल मीडिया पर अपनी राय शेयर करती रहती हैं। एक्ट्रेस आमतौर पर नेपोटिज्म को लेकर बोलती दिखाई देती हैं। इस बार कंगना ने ट्विंकल खन्ना को आड़े हाथों लिया है और नेपोटिज्म का दावा किया है। एक इवेंट में ट्विंकल ने अपने पति की तुलना प्लास्टिक बैग से की थी। ऐसे में कंगना ट्विंकल से काफी नाराज नजर आईं। कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'ये लोग जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, अपने पतियों को प्लास्टिक का थैला कह रहे हैं। क्या ऐसा कहकर वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने अच्छे हैं? चांदी के चम्मच के साथ जन्मे इन नेपो बच्चों को सोने की थाली में फिल्मी करियर दिया गया, इसका तो इन्हें सम्मान है नहीं, कम से कम मदरहुड लाइफ ही एंजॉय करें, लेकिन यह भी इन्हें अभिशाप लग रहा है। यह आखिर बनना क्या चाहते हैं? सब्जियां? क्या यह फेमिनिज्म है?इस बीच, एक कार्यक्रम में ट्विंकल ने कहा, हम कभी भी समानता और नारीवाद के बारे में बात नहीं करते हैं। अगर हम देखें तो हमें पुरुषों की जरूरत नहीं है। हमें एक अच्छे प्लास्टिक बैग की जरूरत है और हमें अपने जीवन में पुरुषों की जरूरत है। मैं इसी मानसिकता के साथ बड़ी हुई हूं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों के बाल अधिक होते हैं। वे जल्दी झड़ जाते हैं। लंबे समय तक मुझे लगा कि पुरुषों का कोई खास उपयोग नहीं है।

इन 10 किरदारों में 'सीमा', 'सुजाता', 'बंदिनी' के अक्स, भंसाली को समझने के 10 सीधे मंत्र

दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक 'भारत एक खोज' के संपादन से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले मौजूदा दौर के शो मैन निर्माता-निर्देशक संजय लीला भंसाली की एक अलग सी शख्सियत के मुंबई में किस्से हजार हैं। उनके साथ काम करने वालों के किस्से अमावस हैं तो उनकी फिल्में देखने वालों के चांद। भंसाली ने अपनी पहली हिट फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' से जो अपना सा सिनेमा, हिंदी सिनेमा में गढ़ा है, उनके कद्रदान इस सफर में साथ आए सात राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारो और 12 फिल्मफेयर पुरस्कारों संग मिलकर एक अलग कारवां हो चुके हैं। संजय का ओटीटी डेब्यू जल्द ही नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज 'हीरामंडी' से होने वाला है। 60 के हो चुके संजय में अब भी बचों जैसी जिद है, किशोरों जैसा जोश है, और है, जवानी जैसी अपनी अलग कहानी। उम्र के चौथपन में भी वह अपने सिनेमा में 'सीमा', 'सुजाता' और 'बंदिनी' तलाशते हैं। इस तलाश में संजय ने हिंदी सिनेमा में चंद बेहतरीन महिला किरदार गढ़े हैं, आइए देखते हैं उनकी झलक, शुरुआत पिछली फिल्म की गंगूबाई से.. फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में अभिनेत्री आलिया भट्ट का बहुत ही मजबूत और सशक्त किरदार रहा है। इस फिल्म की कहानी एस. हुसैन जैदी की लिखी किताब माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई पर आधारित है। फिल्म में गंगूबाई एक यौनकर्मी के रूप में शरुआत करती है और बाद में सभी लड़कियों के हक के लिए आवाज उठाती है। एक महिला माफिया डॉन और कमाठीपुरा में एक वेश्यालय की मालकिन की भूमिका में आलिया भट्ट ने इस किरदार को जीवंत कर दिया। फिल्म पद्मावत में रणवीर सिंह और शाहिद कपूर जैसे अभिनेताओं के बीच दीपिका पादुकोण का किरदार फिल्म का मुख्य आकर्षण था। पद्मावती की सुंदरता की खबर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची, जिसने रानी को पकड़ने की इछा से प्रेरित होकर चित्तौड़ को घेर लिया। रानी पद्मावती ने खुद को दुष्ट शासक अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में सौंपने के बजाय जौहर (आत्मदाह) करने का फैसला किया।

रेस्टोरेंट में अजनबी ने चुकाया सोनू सूद का बिल... एक्टर ने शेयर किया प्यारा पोस्ट

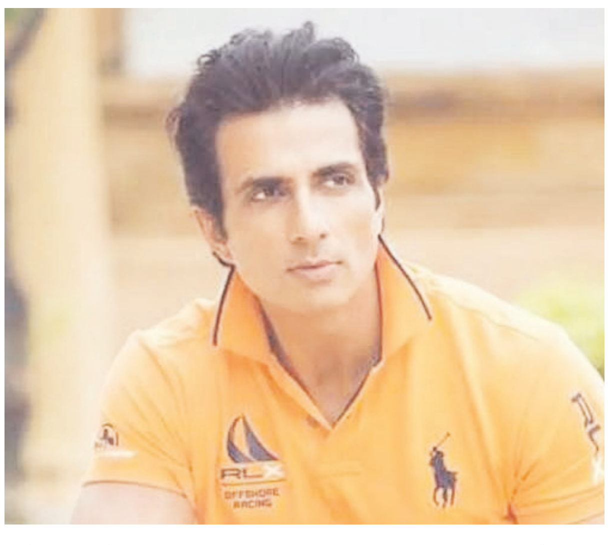

मुंबई। कोविड-19 महामारी के दौरान अभिनेता सोनू सूद ने लोगों के लिए जो नेक काम किया है। उसके लिए दुनिया भर के लोग उनकी तारीफ करने में नहीं थकते हैं। सोनू सूद फिल्म इंडस्ट्री के सबसे दमदार एक्टर में से एक हैं। अपनी दरियादिली से सभी के दिल में जगह बनने वाले सोनू सूद एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने गरीबों, प्रवासी मजदूरों और कामगारों की मदद की, जिसके बाद वह लोगों के मसीहा कहे जाने लगे। इस बीच अब एक अजनबी शख्स ने सोनू सूद के लिए कुछ ऐसा किया है, जिसे एक्टर भी खुशी से गदगद हो गए और एक प्यारा सा रिएक्शन नोट शेयर कया है।

सोनू सूद ने अजनबी के लिए शेयर किया पोस्ट- सोनू सूद के नेक काम में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी उनका सहयोग भी किया। इस पहल के बाद सोनू का एक बड़ा फैनबेस बन गया है जो अक्सर एक्टर के लिए कुछ न कुछ ऐसा करते हैं, जिससे वह हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर सोनू सूद ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक अनजान शख्स ने जो उनके लिए नोट लिखा है, उसकी झलक दिखाई है। सोशल मीडिया पर एक्टर सोनू सूद का ये पोस्ट तेजी से वायरल होते ही चर्चा में आ गया है।

अजनबी ने चुकाया सोनू सूद का बिल- सोनू सूद ने एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि किसी अनजान शख्स ने रेस्टोरेंट में उनका पूरा डिनर का बिल भरा और एक प्यारा सा नोट उनके लिए छोड़कर चला गया। इस नोट में सोनू द्वारा किए गए अच्छे काम की सराहना की गई। सोनू ने इस नोट और रेस्टोरेंट की झलक पोस्ट में शेयर की है। सोनू सूद ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'मुझे नहीं पता कि किसने किया हैज लेकिन किसी ने रेस्टोरेंट में हमारे डिनर का बिल भरा और एक नोट छोड़ाज मेरे लिए इतना प्यार देखकर मुजे बहुत अच्छा लगा। आपका धन्यवाद दोस्तज मेरे लिए यह सब बहुत मायने रखता है।'

कलेक्टर के निर्देश पे चलाया गया मिलावट से मुक्ति अभियान

गठित दल ने 10 घरेलू सिलेंडर जप्त एवं एमआरपी से अधिक मूल्य पर प्रकरण दर्ज

सुरेश मुलेवा। सिटी चीफ

झाबुआ, मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा द्वारा गठित दल ने 23 फरवरी 2024 को झाबुआ नगर में कार्यवाही कर 10 घरेलू सिलेंडर जप्त किए तथा तीन खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए गए हैं साथ ही विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत अधिक मूल्य पर दूध विक्रय करते पाए जाने की स्थिति में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है । नगर में टीम द्वारा झाबुआ के बस स्टैंड से दूध की थैली होटल जय अंबे से क्रय की गई, जिस पर एमआरपी मूल्य ? 55 अंकित था विक्रेता द्वारा दूध थैली को 62 रुपए में विक्रय करने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया वही उक्त होटल पर घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग करते पाए जाने की स्थिति में सिलेंडर जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया टीम द्वारा राजगढ़ नाका स्थित जोशी भोजनालय, भिलिस्तान होटल भंडारी पेट्रोल पंप चौराहा, शिव रेस्टोरेंट भंडारी पेट्रोल पंप के पास, श्रीराम होटल तथा गादिया कॉलोनी चौराहा स्थित आरती होटल से कुल 10 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किए गए हैं। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यवाही कर खाद्य रंग बेसन तथा बादाम शेक के नमूने जांच के लिए लिए हैं एवं बस स्टैंड स्थित होटल जय अंबे पर एक्सपायरी सोहन पपड़ी तथा सेव नमकीन पाए जाने की स्थिति में लगभग 10 किलो की मात्रा में खाद्य पदार्थ मौके पर ही नष्ट करवाया गया हैं।

खाद्य सुरक्षा, नापतौल विभाग एवं खाद्य विभाग की थान्दला में संयुक्त कार्यवाही

मध्य प्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा के निर्देशानुसार झाबुआ में नापतोल विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग एवं खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का संयुक्त द्वारा थान्दला में कार्यवाही की गई। इस दौरान नापतोल निरीक्षक द्वारा अल अनवर हार्डवेयर बाय पास रोड थांदला इलेक्ट्रॉनिक तौलकाँटा सत्यापित नहीं पाए जाने पर तौलकाँटा जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होटल कनिष्क वेज, नॉन वेज ढाबा, दिलीप ढाबा काकनवानी बाईपास, होटल लजीज कुशलगढ़ रोड, होटल न्यू भाग्योदय खवासा रोड चैनपुरी, धनपाल किराना खवासा रोड चैनपुरी, माधव किराना स्टोर खवासा रोड चैनपुरी आदि होटल एवं किराना दुकानों के निरीक्षण कर घी, कोल्डड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स एवं सेव के नमूने जाँच के लिए गए है। साथ ही सम्भाग स्तरीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा कुल 32 खाद्य पदार्थों के मौके पर ही सेकरीन, खाद्य रंग के परीक्षण किये गए।

जिले में टीम की कार्यवाही लगातार अभियान के रूप मैं जारी रहेगी। संयुक्त दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राहुल सिंह अलावा, नापतोल निरीक्षक श्री कपिल कदम, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी झाबुआ श्री संदीप राठौर, श्रम सहायक श्री संजय पांचाल एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग श्री विजय चौहान झाबुआ उपस्थित रहे।

स्टेट प्रेस क्लब से रूबरु होकर बोले नवागत पुलिस अधीक्षक श्री शुक्ला

सोशल पुलिसिंग से समाज के हर वर्ग को जोड़ेंगे, अपराधों पर कसेंगे शिकंजा, सामाजिक कुरीतियों ओर नशे के खिलाफ चलाया जाएगा विशेष अभियान

सुरेश मुलेवा । सिटी चीफ

झाबुआ, 21 फरवरी को झाबुआ में पुलिस अधीक्षक के रूप में पदम विलोचन शुक्ला ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान स्टेट प्रेस क्लब मप्र टीम झाबुआ के द्वारा नवागत पुलिस अधीक्षक श्री शुक्ला का स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर नवागत पुलिस अधीक्षक स्टेट प्रेस क्लब से रूबरू हुए ओर सवालों का जवाब देते हुए बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि सोशल पुलिसिंग के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़कर अपराधों पर शिकंजा कसा जाए। क्योंकि सोशल पुलिसिंग, पुलिस और आम लोगों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देती है। इसका मकसद, पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करना है। सोशल पुलिसिंग, पुलिस और समाज के बीच पारदर्शिता, बातचीत, और सहयोग की नींव रखती है। नवागत पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को लेकर भी एक विशेष अभियान

चलाया जाएगा। जिसमें सामाजिक संगठनों, एनजीओ, शासकीय संस्थाओं के साथ लेकर सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने हेतु जमीनी स्तर पर कार्य किया जाएगा। ताकि जिले से सामाजिक कुरीतियों को खत्म किया जा सके। वहीं जिले में नशे के खिलाफ भी ऐसे अभियान चलाये जाएंगे, जिससे विशेष कर युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। नशे के खिलाफ चलने वाले अभियानों में भी सोशल पुलिसिंग की अहम भूमिका रहेगी। आगामी दिनों में जिले में भगोरिया पर्व की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में पुलिस के द्वारा जिले में विशेष पुलिस बल तैनात कर भगोरिया पर्व को संपन्न करवाया जाएगा। पुलिस के द्वारा ऐसी व्यवस्थाए की जाएगी ताकि जिले में भगोरिया पर्व शांतिपूर्ण ओर पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा सके। आमजन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

इंदौर कमिश्नर द्वारा 29 फरवरी के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई बैठक

बैठक में भूमि पूजन एवं विभिन्न कार्यों के लोकार्पण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए

सुरेश मुलेवा। सिटी चीफ

झाबुआ, इंदौर कमिश्नर श्री माल सिंह द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 1८ के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली गई। श्री मालसिंह द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वी सी के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को प्रस्तावित कार्यक्रम जिनमें विभिन्न कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन एवं शासकीय कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही राजस्व महाअभियान के संबंध में भी निर्देश दिए गए। संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स से कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में जानकारी ली गई। अपर कलेक्टर श्री एस.एस. मुजाल्दा द्वारा बताया गया कि जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, जनजाति कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के प्रस्तावित कुल 17 कार्यों का लोकार्पण किया जाना है। जल संसाधन विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं ग्रामीण यात्रीकी सेवा विभाग में कुल चार कार्य प्रस्तावित है जिनकी लागत 1639.96 लाख है। यह कार्यक्रम झाबुआ जिले की तीन विधानसभा झाबुआ, थांदला, एवं पेटलावद में आयोजित किया जाकर लाइव प्रसारण की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही सभी नगरीय निकाय एवं समस्त पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान जिले से संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

नए नंबर के कॉल रिसीव से पहले स्क्रीन पर दिख जाएगा नाम, बड़े बदलाव की तैयारी

नई दिल्ली। अगर सबकुछ ठीक रहा तो आप फोन पर किसी नए नंबर के कॉल को रिसीव करने से पहले उसका नाम देख सकेंगे। दरअसल, दूरसंचार नियामक ट्राई ने टेलीकॉम नेटवर्क में कॉल करने वाले शख्स का नाम फोन स्क्रीन पर दिखाने वाली सेवा शुरू करने की सिफारिश की है।

ट्राई ने की सिफारिश भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपनी सिफारिश में कहा कि 'कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन' (सीएनएपी) अनुपूरक सेवा के तहत मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम प्रदर्शित करने की व्यवस्था शुरू की जाए। हालांकि यह सुविधा ग्राहक के अनुरोध पर ही सभी टेलीकॉम कंपनियां मुहैया कराएंगी। इस सुविधा के शुरू होने पर अक्सर आने वाली अनचाही कॉल से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलेगी। सीएनएपी सुविधा चालू होने पर ग्राहक अपने फोन की स्क्रीन पर कॉलर का

नाम देख पाएगा।

कैसे शुरू हो सुविधा ट्राई ने कहा कि सरकार को एक तय तारीख के बाद भारत में बेचे जाने वाले सभी फोन में सीएनएपी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को उपयुक्त निर्देश जारी करना चाहिए। मोबाइल फोन कनेक्शन लेते समय भरे जाने वाले ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) में दिए गए नाम एवं पहचान विवरण का इस्तेमाल सीएनएपी सर्विस के दौरान किया जा सकता है।

ट्रूकॉलर जैसे ऐप देते हैं सुविधा जहां देसी स्मार्टफोन टूल और ट्रूकॉलर एवं भारत कॉलर जैसे ऐप भी कॉल करने वाले के नाम की पहचान और स्पैम पहचान की सुविधाएं देते हैं। लेकिन ये सेवाएं लोगों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित हैं जो हमेशा विश्वसनीय नहीं होती हैं। दूरसंचार नियामक ने सुझाव दिया कि सभी एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर अपने टेलीफोन ग्राहकों को उनके अनुरोध पर सीएनएपी सेवा मुहैया कराएं। बता दें कि ट्राई ने नवंबर, 2022 में इस संबंध में एक परामर्श पत्र जारी कर हितधारकों, जनता और उद्योग की टिप्पणियां मांगी थीं। बहरहाल, यह नई सुविधा कब से लागू होगी, यह सरकार को तय करना है।

तीसरी तिमाही में 6.4 फीसदी रह सकती है विकास दर, 29 फरवरी को आएंगे GDP आंकड़े

नई दिल्ली। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 6.4 फीसदी रहने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक, विनिर्माण व कंस्ट्रक्शन क्षेत्र जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करेंगे। सरकार 29 फरवरी को जीडीपी के आंकड़े जारी करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, सख्त मौद्रिक नीतियों और अन्य चुनौतियों के बीच दुनिया में मंदी का खतरा बना हुआ है। इनसे वैश्विक विकास प्रभावित होने का जोखिम है। घरेलू स्तर पर लचीलेपन के कारण भारतीय जीडीपी अन्य प्रमुखअर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 6.8 फीसदी की दर से बढ़ सकती है। 2024-25 में यह 6.75-6.8 फीसदी रह सकती है। हालांकि, विपरीत वैश्विक स्थितियों के कारण निर्यात प्रभावित हो सकता है।

कृषि और उद्योग क्षेत्र में धीमी रहेगी वृद्धि रिपोर्ट के अनुसार, कषि और उद्योग क्षेत्र में

धीमी वृद्धि रहेगी। सेवा क्षेत्र में तेज वृद्धि की उम्मीद है। औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर जहां 8 फीसदी रह सकती है, वहीं खनन और विनिर्माण की वृद्धि दर छह और 8.6 फीसदी रह सकती है। हालांकि, दूसरी तिमाही की तुलना में यह कम रह सकती है। ट्रैक्टर और दोपहिया वाहनों की बिक्री में नरमी से ग्रामीण मांग धीमी होने की आशंका है। हालांकि, जनवरी में ई-वे बिल जेनरेशन में वृद्धि से सेवाओं को कुछ मदद मिलेगी।

सेवा क्षेत्र ~ 6.7 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगा आगे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी रिपोर्ट में कहा, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में निर्माण क्षेत्र की विकास दर बेहतर रह सकती है। इस दौरान सेवा क्षेत्र 6.7 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है।? दूसरी तिमाही में इसकी वृद्धि दर 5.8 फीसदी रही थी। तीसरी तिमाही के दौरान कारोबार, होटल और परिवहन क्षेत्र की विकास दर 6.4 फीसदी रहने का अनुमान है। कर्ज वितरण ?की अच्छी स्थिति से वित्तीय क्षेत्र 6.5 फीसदी की दर से आगे बढ़ सकता है।

हम किसानों से जुड़े मुद्दों पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं: निर्मला सीतारमण

-वित्त पोषित योजनाओं के तहत 1,000 करोड़ रुपये के ऋण किए वितरित

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपारेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि हम किसानों से जुड़े मुद्दों पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान को जो उचित सुविधा और कर्ज मिलना चाहिए, वह तो मिल ही रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के महराजगंज में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। सीतारमण ने आज विभिन्न सरकारी वित्त पोषित योजनाओं के तहत 1,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मत्स्यपालन के लिए भी एक अलग विभाग बनाया है, जिसके कारण महाराजगंज में पशुपालन और मत्स्यपालन को भी अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने मंत्रियों की 3 सदस्यीय

समिति बनाई है, जो किसानों से बातचीत कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर कदम उठाया है और वह छोटे से छोटे किसानों के लिए भी काम करते हैं। यूरिया की कीमत 300 रुपये से 3,000 रुपये प्रति बोरी तक पहुंच गई है लेकिन आज भी किसान इसे 300 रुपये में खरीद रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हम किसानों से जुड़े मुद्दों पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराजगंज में 'एक जिला, एक उत्पाद' के तहत लकड़ी का काम करने वाले को भी पीएमविश्वकर्मा के तहत प्रशिक्षण मिल रहा है, जिसके दौरान रोज 500 रुपये दिए जाते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि फिर प्रशिक्षण होने के बाद उनको काम बढ़ाने के लिए टूलकिट और ऋण की सुविधा भी मिलती है। सीतारमण ने महराजगंज में एक जनसभा को सबोधित करते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि 2027 तक भारत दुनिया के तीन अग्रणी देशों में शामिल हो।

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पुरस्कार वितरण के साथ हुआ वार्षिकोत्सव का समापन

प्रतिभाओं का किया गया सम्मान

पियूष अग्रवाल । सिटी चीफ
खरगोन, जिले के अग्रणी महाविद्यालय में तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव का समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार के मुख्य आतिथ्य तथा जन भागीदारी समिति अध्यक्ष दीपक कानूनगो की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। स्वागत भाषण में प्राचार्य डॉ. आरएस देवड़ा ने अतिथियों का परिचय देते हुए 20 वर्षों का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में 5 जनभागीदारी समिति अध्यक्षों परशराम डंडीर, बाबूलाल महाजन, नरेन्द्र सिंह राठौर, बालकृष्ण पाटीदार तथा दीपक कानूनगो के कार्यकाल में महाविद्यालय में हुए विकास कार्यों यथा बाउंड्रीवॉल निर्माण, कंप्यूटर्स लैब, कैंटीन निर्माण, मुख्य द्वार निर्माण, वाणिज्य भवन, मुख्य भवन, इंडोर स्पोर्ट्स हाल निर्माण आदि की जानकारी दी तथा इस के लिए तात्कालिक विधायक, जनभागीदारी समिति, जिला कलेक्टर, विविध अधिकारियों के योगदान को स्पष्ट किया।

पूर्व जनभागीदारी अध्यक्ष नरेंद्र राठौर ने खरगोन महाविद्यालय का विश्वविद्यालय में संविलियन होने पर हर्ष व्यक्त किया। पूर्व विधायक परशराम डण्डीर ने अपने कार्यकाल का संस्मरण करते हुए महाविद्यालय के विकास कार्यों के लिए फीस स्ट्रक्चर में बदलाव का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्तमान विकास तक पहुँचने के लिए यह आवश्यक कदम था।

पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन ने महाविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने 1976 से 2008 तक के कार्यकाल की प्रगति और अपने संस्मरण बताते हुए कहा कि स्वर्णिम भारत का स्वप्न फलीभूत हो रहा है। प्राचार्य डॉ. देवड़ा के कार्यकाल को उनकी कड़ी मेहनत, लगन, और समर्पण के कारण महाविद्यालय की विकास यात्रा का स्वर्णिम काल बताया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व वर्तमान लोकप्रिय विधायक पाटीदार ने विद्यार्थियों को प्रेरणा देते हुए कहा कि विश्वपटल पर भारत को सिरमौर बनाने का दायित्व युवाओं का है। अतः इसके लिए युवाओं को संकल्प लेकर कार्य करना होगा। अपने विदेश भ्रमण के अनुभव साझा करते हुए कहा कि विश्व मे भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ है। खरगोन शहर में विश्वविद्यालय का बनना इस क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है तथा इसके खुलने से सभी विषयों की पढ़ाई जिले में ही संभव हो सकेगी।

पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में वर्षभर में एनएसएस, एनसीसी, क्रीड़ा विभाग, मतदान जागरूकता, समाज कार्य विभाग, शोध कार्य, आजादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय युवा दिवस के अंतर्गत आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को तथा यूजीसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक कार्यक्रम के विजेता प्रतिभागी, सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले लगभग 250 से अधिक छात्र छात्राओं को प्रमाणपत्र, स्मृति चिन्ह तथा मेडल से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन नगर पालिका एवं जनजातीय विभाग का विशेष सहयोग रहा। दीपक कानूनगो ने स्नेह सम्मेलन के आयोजन और विद्यार्थियों द्वारा बढ़-चढ़कर भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। स्नेह सम्मेलन प्रभारी डॉ. जीएस चौहान ने कार्यक्रम में पधारे अतिथियों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ रंजीता पाटीदार, प्रो. ऐश्वर्या दिलावरे एवं प्रो संजय कोचक द्वारा किया गया।

इस कार्यक्रम में सदस्य मुकेश बिडारे, सचिन पाठक, शीतल राठौर, हिमांशु ठाकुर, कालूसिंह, माया खोड़े, श्रीमती मीना कोचले, महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, एनसीसी एवं एनएसएस स्वयंसेवक, बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, महाविद्यालयीन कर्मचारी आदि उपस्थित थे।

खरगोन जिले की मदिरा दुकानों का निष्पादन नवीनीकरण लॉटरी के माध्यम से किया

कलेक्टर अरविंद दुबे की अध्यक्षता में हुआ निष्पादन

पियूष अग्रवाल। सिटी चीफ
खरगोन, खरगोन जिले की मदिरा दुकानों का निष्पादन नवीनीकरण/लॉटरी के माध्यम से आज 23 फरवरी 2024 को किया गया। जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि जिले में कुल 83 मदिरा दुकानें 19 मदिरा समूहों में विभाजित है। जिनका कुल आरक्षित मूल्य 2791124938 रुपए हैं। जिनमें से 14 मदिरा समूहों द्वारा 15 प्रतिशत मूल्यवृद्धि के साथ नवीनीकरण कराया गया एवं नान्द्रा मदिरा समूह का निष्पादन लॉटरी के माध्यम से किया गया। इस प्रकार नवीनीकरण एवं लॉटरी के

माध्यम से कुल आरक्षित मूल्य का 84.68 प्रतिशत रूपये 2363502751 रुपए का निष्पादन सम्पन्न हुआ। आबकारी अधिकारी तिवारी ने बताया कि शेष 15.32 प्रतिशत 427622187 रुपए के कुल चार मदिरा समूहों की 17 मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाना है। जिसके लिए 27 फरवरी से 04 मार्च 2024 तक ई-टेण्डर डाले जा सकेंगे।

दमोह में बड़ी धूमधाम से मनाई गई संत गाडगे जी महाराज की 148वीं जयंती

माल्या अर्पण कर शहर में निकाला विशाल जुलूस

धीरज कुमार अहीरवाल। सिटी चीफ दमोह, स्वच्छ भारत के जनक संत गाडगे जी महाराज की 148वीं जयंती आज बड़ी धूमधाम से रजक समाज द्वारा मनाई गई द्य समाज के सजातीय बंधु शहर के मानस भवन के पास एकत्रित होकर संत गाडगे जी महाराज के चित्र पर माल्या अर्पण किया एवं एक विशाल जुलूस शहर के विभिन्न मार्गो से होते हुए बड़ी देवी में समापन हुआ जलूस मे संत गाडगे जी

महाराज के चित्र के साथ बड़ी संख्या में समाज के युवा बुजुर्ग महिलाएं शामिल हुए उनके द्वारा दिए गए संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं।

निर्माण कार्यों में तेजी लायें और गुणवत्ता बनाये रखें- अनुराग वर्मा

कलेक्टर ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का किया स्थल निरीक्षण

विवेक मिश्रा। सिटी चीफ
सतना, कलेक्टर अनुराग वर्मा ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को सतना शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी की विकास परियोजनाओं के कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता देखी और कार्यों में तेजी लाकर जून 2024 तक सभी स्मार्ट सिटी के कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेने के निर्देश दिये। इस मौके पर आयुक्त नगर निगम अभिषेक गहलोत, उपायुक्त भूपेन्द्र देव परमार, कार्यपालन यंत्री अरुण तिवारी, कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड महेश घनघोरिया सहित स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी मौजूद रहे।

कलेक्टर श्री वर्मा ने अपना निरीक्षण भ्रमण दादा सुखेन्द्र सिंह स्टेडियम के कार्यों के निरीक्षण से शुरू किया। उन्होंने 8 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम को सर्व सुविधायुक्त बनाने किये जा रहे ग्राउंड वर्क और इंडोर गेम्स के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने 7 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के आधार पर बनाए जा रहे धवारी क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य का अवलोकन किया और कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने महदेवा में बन रहे नगर निगम के सीवरेज प्लांट के एचटीपी का भी निरीक्षण किया। कमिश्नर नगर निगम ने बताया कि 15 एमएलडी क्षमता के एचटीपी में 3 एमएलडी घरेलू जल निकासी का सीवेज और शेष गंदे नाले का सीवेज यहां एकत्र कर साफ किया जायेगा। एचटीपी की गतिविधियों की सतत निगरानी स्काडा सिस्टम से की जायेगी।

कलेक्टर ने सोनौरा उतैली में 35 करोड़ की लागत से बन रहे सर्व-सुविधायुक्त मल्टी स्पोर्ट कांप्लेक्स के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। ताकि जून 2024 तक काम्पलेक्स का कार्य पूर्ण किया जा सके। उन्होंने स्मार्ट सिटी द्वारा 31.69 करोड़ की लागत से निर्मित किये गये नेक्टर झील का भी निरीक्षण किया तथा उसके आगे संचालन संबंधी जानकारी ली। कलेक्टर ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा 31 करोड़ 15 लाख रुपए लागत से बायपास मैहर रोड के समीप बनाये जा रहे इंटर स्टेट बस टर्मिनल्स के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को कार्यों में प्रगति लाने की निर्देश के साथ ही बस स्टैंड के आगमन और निकासी मार्ग, हरित पट्टी के संबंध में दिशा-निर्देश दिये। बाद में कलेक्टर ने पुरानी विश्वास राव सब्जी मंडी के समीप हाउसिंग बोर्ड द्वारा 9 करोड़ 16 लाख रुपये लागत से बनाए जा रहे कम्युनिटी हॉल के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि कम्युनिटी हाल में 25-25 दुकानें भी बनाई जा रही हैं। ऊपरी तल पर 11 कमरों का निर्माण किया जा रहा है। कम्युनिटी हाल में अंदर लगभग 10 हजार वर्ग फीट का वृहद कक्ष होगा। यहां 700 से 800 व्यक्तियों के बैठने और मांगलिक कार्यक्रम करने की व्यवस्था रहेगी। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि आईएसबीटी और कम्युनिटी हॉल के निर्माण कार्य जून 2024 तक कम्पलीट कर लिये जायेंगे।

लोकसभा सांसद गजेंद्रसिंह पटेल ने किया सामुदायिक भवनों का भूमिपूजन

कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष मनोहर जी अवास्या एवं अन्य सदस्य शामिल रहे

अशोक राठौर । सिटी चीफ
बड़वानी, शुक्रवार को लोकसभा सांसद गजेंद्रसिंह पटेल ने राजपुर विधानसभा के तलवाड़ाडेब मण्डल के ग्राम पान्या में 40 लाख,मंडवाड़ा में 20 लाख,हरणगाँव में 20 लाख,सुराना बाड़ी में 10 लाख, फत्यापुर में 10 लाख,बावड़िया में 20 लाख,उचवाद में 20 लाख,रसवा में 10 लाख, लखनगाँव में 10 लाख इस प्रकार से कुल राशि 1 करोड़ 60 लाख के लगभग के कार्यों का भूमिपूजन किया । ग्रामों में सामाजिक कार्य सुविधा तथा व्यवस्था एव सामुदायिक सशक्तीकरण के लिये सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास सबका प्रयास कि

दिशा में उपलब्धि है।

कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष मनोहर जी अवास्या, मण्डल अध्यक्ष कल्याण जी सोलंकी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रमेश जी यादव, जनपद उपाध्यक्ष नारायण जी,सुरेंद्र जी गेहलोत, अंजड़ मण्डल अध्यक्ष राजा जी चौहान, भगतसिंह सोलंकी, भारत यादव, राधेश्यम जी धनगर, हरीश सोलंकी, अशोक राठौर।

झाबुआ में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ

सुरेश मुलेवा। सिटी चीफ झाबुआ, स्थानीय शहीद चन्द्रशेखर आजाद, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ के खेल मैदान पर सांसद खेल महोत्सव 23 फरवरी 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया एवं वन पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री म.प्र. शासन श्री नागरसिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर आयोजक सांसद श्री गुमानसिहं डामोर उपस्थित रहे। कार्यकम का प्रारंभ माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर अतिथियों के द्वारा किया गया।

महिलाओं के प्रति खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 23 फरवरी 2024 को महिला कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गयी। जिसमें जिले के शासकीय महावीर महाविद्यालय पेटलावद, शासकीय कन्या महाविद्यालय झाबुआ, शासकीय आदर्श महाविद्यालय झाबुआ, शहीद चन्द्रशेखर आजाद, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ के दलों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. गोपाल भूरिया ने किया तथा आभार डॉ. बी.डी. शर्मा ने माना। इस अवसर पर संस्था प्रमुख एवं प्राचार्य डॉ. जे.सी. सिन्हा, कन्या महाविद्यालय प्राचार्य प्रो. सी.एस. चौहान, प्रो. वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. अंजना सोलंकी, डॉ. संजू गांधी, प्रो. जे.एस. भूरिया एवं समस्त महाविद्यालय स्टाफ तथा बडी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

शहडोल में रेत खनन के मामले में वैध ठेकेदार का अवैध खनन

प्रशासनिक अधिकारियों ने की सख्त कार्रवाई

मोहम्मद मुनीर। सिटी चीफ
शहडोल, लगातार रेत ठेका कंपनी का लीज से बढ़कर खनन जारी है और जब भी यह वैध? ठेकेदार का अवैध खनन पर कैसे पर्देदारी की जाती है गुरुवार की घटनाक्रम से समझने की आवश्यकता है दरअसल मीडिया पर वायरल खबरों के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की फौज सहकार ग्लोबल कंपनी लिमिटेड के रेत खनन की निगरानी करने, जीओ टैगिंग और तय लीज क्षेत्र की फ्लैगिंग की जांच करने की जगह महज खानापूर्ति को देर शाम खनिज विभाग का अमला चाका घाट की प्रकाशित खबर को ही अंडे हाथ लेते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी उक्त खनन मामले में एक बड़े अखबार की खबर को कटघरे में खड़ा कर दिया और सहकार ग्लोबल कंपनी को कुछ ऐसे क्लीन चिट दे दी मानो कातिल भी तुम मुंसिफ भी?।

यहां भी हुई अज्ञात पर कार्यवाही.....जनसंपर्क की भेजी खबरों के मुताबिक जिले में रेत के अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर वंदना वैद्य आदेशानुसार आज खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग संयुक्त रूप से जांच किया गया ग्राम बिजौरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल में सोन नदी से रेत का उत्खनन कर नदी के किनारे पर शासकीय भूमि में रेत का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। जांच दल को देखकर अवैध भण्डारणकर्ता मौके से भाग निकले मौके पर अवैध रूप से भंडारित रेत को जप्त किया गया तथा जिले के वैध ठेकेदार मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड मुंबई को 9 डग्गी रेत (45 घन मीटर) सुपुर्दगी में देकर

सुरक्षार्थ उठवाकर रखवाया गया। जिले के स्वीकृत रेत खदान ग्राम चाका घाट में रेत के अवैध उत्खनन/ नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में शिकायत की जांच की गई जांच दौरान रेत का नियम विरुद्ध उत्खनन होते नहीं पाया गया।

यानी आप रेत खनन लीज से बढ़कर कीजिए मीडिया पर वायरल प्रकाशित

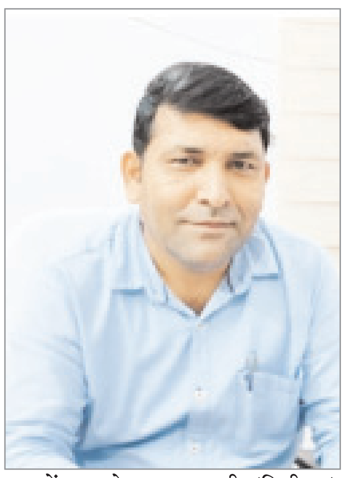

खबरों का बोझ 7-8 डग्गी (मिनीट्रक) नहीं केवल रेत का ढ़ेर पकड़ा और सुपुर्द किया लीज क्षेत्र से बाहर खनन करने वाली वर्तमान में ठेका कंपनी सहकार ग्लोबल को अब ऐसे में आपको समझना जरूरी है कि जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की फौज करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर जिले की खनिज संपदा को लूटते रहने और ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए नियुक्त करती है या अवैध रूप से खनन और परिवहन मामले में निष्पक्ष जांच कार्यवाही कर खनिज संपदा और अरबों रुपए का चूना लगाने वाले लोगों पर कार्यवाही के लिए सरकार लाव-लश्कर की ताक़त के साथ कुर्सी पे बैठाकर रखा है।

मामले में खनिज अधिकारी देवेन्द्र पटले के मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगाकर हालिया जवाब तलाशने की कोशिश लेकिन अब उन्होंने मानों मीडिया सवालों के जवाब ना देना पड़े चुप्पी साध रखी है।

इजराइली बस्तियों को लेकर अमेरिका के रुख में बदलाव कहा- बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं

इंटरनेशनल डेस्क- अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने शुक्रवार को अमेरिका के लगभग 50 वर्ष पुराने उस रुख को दोहराया कि फलस्तीन के कब्जाए गए क्षेत्रों में बसीं इजराइली बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत 'अवैध हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका का मानना है कि बस्तियां इजराइली दायित्वों के अनुरूप नहीं हैं। ब्लिंकन का यह बयान पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के रुख के विपरीत है। बाइडन प्रशासन का यह रुख पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल समर्थक नीतियों से भी अलग है।

अमेरिका-इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा

ब्लिंकन ने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में यह बात कही। पत्रकार ने उनसे उस घोषणा के बारे में पूछा था जिसमें कहा गया था इजराइल फलस्तीन के हमले के जवाब में वेस्ट बैंक में 3,300 से अधिक नए घर बनाएगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तीन साल से अधिक कार्यकाल होने पर ब्लिंकन ने पॉम्पिओ के फैसले को पलटने के लिए यह समय क्यों चुना है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब गाजा में जारी युद्ध को लेकर अमेरिका-इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। साथ ही यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इजराइली कब्जे की वैधता को लेकर सुनवाई कर रहा है।

बस्तियों के विस्तार का विरोध करता है अमेरिका

ब्लिंकन ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कहा कि अमेरिका को इजराइल के धुर दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजालेल स्मोटरिच द्वारा घोषित नयी बस्तियों से संबंधित योजना के बारे में जानकर 'निराशा हुई है। बेजालेल ने यह घोषणा माले अडुमिम बस्ती के निकट कारों पर तीन फलस्तीनी बंदूकधारियों के हमले में एक इजराइली सैनिक की मौत के बाद की है। ब्लिंकन ने हमले की निंदा की, लेकिन कहा कि अमेरिका बस्तियों के विस्तार का विरोध करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका एक बार फिर (पूर्व राष्ट्रपति जिमी) कार्टर के शासनकाल में अपनाए गए कानूनी रुख का पालन करेगा कि बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं हैं।

अमेरिका ने रूस पर लगाए 500 से अधिक नए प्रतिबंध

रूसी विदेश मंत्रालय ने भी लिया कड़ा एक्शन

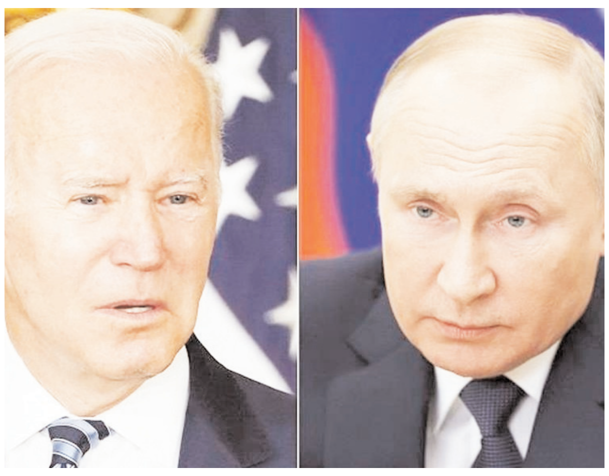

वाशिंगटन: अमेरिका ने यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत के दूसरे वर्ष की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को उसके खिलाफ 500 से अधिक नए प्रतिबंधों की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि रुस के आकर्टिक क्षेत्र में विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की मौत के आलोक में भी प्रतिबंध लगाए गए। वाशिंगटन ने दावा किया कि रूसी सरकार जिम्मेदार थी। बाइडेन ने कहा, %ये प्रतिबंध नवलनी के कारावास से जुड़े व्यक्तियों के साथ-साथ रूस के वित्तीय क्षेत्र, रक्षा औद्योगिक आधार, खरीद नेटवर्क और कई महाद्वीपों में प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों को लक्षित करेंगे।% रूस ने 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किया था। अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए लगाए जाने के बाद रूसी विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है. जारी किए गए बयान में बोला गया है कि रूस में प्रवेश से प्रतिबंधित यूरोपीय संघ के अधिकारियों और नेताओं की सूची को और बढ़ा दिया गया है.

ईरानी सेना ने पाकिस्तान में फिर की सर्जिकल स्ट्राइक

जैश अल अदल का शीर्ष कमांडर ढेर

इंटरनेशनल डेस्क- ईरान और पाकिस्तान के बीच विवाद लगातार जारी है। ईरान ने एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकियों की ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस हमले में जैश अल-अदल के कमांडर इस्माइल शाह बख्श को मार गिराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरानी सेना ने पाकिस्तानी की सीमा में घुसकर सुनियोजित तरीके से आतंकी संगठन जैश अल अदल के शीर्ष कमांडर इस्माइल शाह बख्श और उसके कुछ साथियों को ढेर कर दिया। इससे पहले बीते दिनों ही ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में हवाई हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के खिलाफ जवाबी हमला किया था। इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। कब हुआ जैश अल-अदल का गठन जैश अल अदल का गठन साल 2012 में हुआ था। जैश अल-अदल ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत का एक सुन्नी आतंकी समूह है। इस संगठन को ईरान की सरकार आतंकी संगठन मानती है।ईरान में हुए कई हमलों में इस संगठन का हाथ माना जाता है। पिछले साल दिसंबर में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था। उस हमले में 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस हमले के पीछे भी जैश अल अदल का हाथ बताया गया था।

टीवी एंकर पर फिदा हुई लड़की, दोस्तों की मदद से किया किडनैप, बोली- अब तुमसे ही करूंगी शादी

नैशनल डैस्क - हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 5 स्टार्टअप कंपनियों की लेडी डायरेक्टर एक टीवी एंकर पर इस तरह फिदा हो गई कि उसका अपहरण तक कर लिया। हालांकि, पुलिस ने शनिवार को कहा कि हैदराबाद में एक व्यवसायी महिला को एक टेलीविजन एंकर का पीछा करने और उसका अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महिला के मुताबिक, एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को उस टीवी एंकर के रूप में पेश किया और फिर कथित तौर पर उसे धोखा दिया और पैसे लेकर गायब हो गया।

आखिर क्या है मामला ?

भोगिरेड्डी तृषा नाम की महिला ने टेलीविजन एंकर प्रणव सिस्तला का अपहरण कर लिया। महिला का कहना है कि एंकर की प्रोफाइल के साथ मैट्रिमोनी पर फर्जी अकाउंट बना था। उस शख्स ने उससे 40 लाख लिए और फिर बात करना छोड़ दी। इसके बाद महिला ने एंकर की तलाश की और फिर दोस्तों के साथ मिलकर उसका उपहरण कर लिया। महिला और उसके पांच साथियों को तेलंगाना पुलिस ने 22 फरवरी को गिरफ्तार किया था। जांच में अपराध के बारे में दिलचस्प विवरण सामने आए, क्योंकि महिला ने एंकर की गतिविधियों का पता लगाने के लिए उसकी कार पर एक एयरटैग भी लगाया था। महिला दो साल पहले भारत मैट्रिमोनी वेबसाइट के जरिए चैतन्य रेड्डी नाम के एक अज्ञात व्यक्ति के संपर्क में आई। जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी, उन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर चैट करना शुरू कर दिया और एक समय पर उस व्यक्ति ने अच्छे रिटर्न का वादा करते हुए उससे अपने व्यवसाय में निवेश करने के लिए कहा। पुलिस के अनुसार, महिला ने कथित तौर पर यूपीआई के माध्यम से उस व्यक्ति को 40 लाख रुपये का भुगतान किया, लेकिन पैसे प्राप्त करने के बाद, महिला ने कहा कि अज्ञात व्यक्ति उससे बचने लगा। ठगे जाने का अहसास होने पर महिला ने उस प्रोफाइल पर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क किया, जो प्रणव का निकला। लेकिन प्रणव ने महिला को बताया कि चैतन्य रेड्डी नाम के किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी फोटो का इस्तेमाल किया और भारत मैट्रिमोनी पर फर्जी अकाउंट बनाए और उन्होंने साइबर सेल में शिकायत भी दर्ज कराई।

शादी के लिए अड़ गई थी महिला

पुलिस के मुताबिक, हालांकि महिला ने एंकर को मैसेज भेजना जारी रख। महिला से परेशान होकर एंकर ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद वो महिला एंकर से ही शादी करने के लिए अड़ गई। महिला ने कहा कि वह एंकर से ही शादी करेगी। महिला ने यह सोचकर उसके अपहरण की योजना बनाई कि बाद में वह मामले को सुलझा सकती है। इसके बाद महिला ने 4 लोगों की मदद से एंकर का अपहरण करने का प्लान तैयार किया। उसने अपने कार्यालय में काम करने वाले एक अन्य व्यक्ति को अपराध के लिए शामिल किया और उसे 50,000 रुपए की पेशकश की। 11 फरवरी को, 4 लोगों ने एंकर का अपहरण कर लिया और उसे अपने कार्यालय में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ मारपीट की। पुलिस के अनुसार, प्रणव ने महिला से अनुरोध किया कि वह उसकी कॉल का जवाब देगा और इसके बाद महिला ने उसे जाने दिया। बाद में उन्होंने उप्पल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और धारा 363 (अपहरण), 341 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत तरीके से कारावास) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

स्वीडन की सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय में गैस रिसाव

500 लोगों को निकाला गया बाहर

स्टाकहोम: स्वीडन की सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय में शुक्रवार को गैस रसीव के संदेह के चलते अधिकारियों द्वारा लगभग 500 लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया। स्वीडन के प्रसारक 'टीवी-4 की खबर में यह जानकारी दी गई। पुलिस प्रवक्ता एंडर्स ब्रिंजल्सन ने 'टीटी समाचार एजेंसी को बताया कि आपातकालीन सेवा विभाग ने ''गैस रिसाव के संदेह के चलते पूरी इमारत को खाली कराने का फैसला किया, लेकिन इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। स्टॉकहोम क्षेत्र के मुख्य चिकित्सक पैट्रिक सोडरबर्ग ने 'टीटी को बताया कि पांच लोगों को सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल के वीडियो में सूचना पाकर सबसे पहले पहुंचे बचावकर्मी और पुलिस अधिकारी गैस से बचाव के लिए मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं। स्वीडन के मीडिया की खबरों के अनुसार घटना वाली इमारत के पांच सौ मीटर के दायरे को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। स्वीडन सुरक्षा सेवा (एसएपीओ) के मुख्यालय के आसपास के क्षेत्र में लोगों को अपने घरों और प्रतिष्ठानों की खिड़कियां बंद रखने को कहा गया है। एजेंसी का मुख्यालय स्टाकहोम के ठीक उत्तर में सोलना में स्थित है।

असम सरकार ने खत्म किया मुस्लिम विवाह एवं तलाक कानून, सीएम बोले- इससे रुकेंगे बाल विवाह

नेशनल डेस्क- असम सरकार ने शुक्रवार को कैबिन मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर रोक के लिए मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून, 1935 खत्म कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा 23 फरवरी को असम कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए वर्षों पुराने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया गया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए हैं, तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। यह असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में अहम कदम है। कैबिनेट मंत्री जयंत बरुआ बोले- वहीं, कैबिनेट मंत्री जयंत बरुआ ने मीडिया से बातचीत में कहा, असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 के आधार पर 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार अब भी राज्य में मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण और तलाक कर रहे थे। इसे निरस्त कर दिया गया है। आज की कैबिनेट (बैठक) ने इस एक्ट को हटा दिया है जिसके बाद आज के बाद इस एक्ट के जरिए मुस्लिम विवाह पंजीकरण या तलाक का पंजीकरण नहीं हो सकेगा। हमारे पास एक विशेष विवाह अधिनियम है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत हों। सरकार के विरोध में मौलाना बदरुद्दीन अजमल- जानकारी के लिए बता दें कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सरकार के इस फैसले के विरोध में हैं। उनका कहना है कि बहुविवाह मुस्लिम समुदायों के अलावा अन्य समुदायों में होता है। ऐसे में सिर्फ मुस्लिमों को निशाना बनाना सही नहीं है। बाल विवाह के सरकार ला सकती है कानून- असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाने पर भी विचार कर रही है।

प्रशांत किशोर का दावा- लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए 100 का आंकड़ा पार करना मुश्किल, बीजेपी को लेकर भी कही यह बात

नई दिल्ली: जानेमाने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए 100 सीट का आंकड़ा पार करना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने समाचार चैनल टाइम्स नाउ के साथ बातचीत में यह भी कहा कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 370 सीट तक पहुंचने की संभावना नहीं है, हालांकि वह पश्चिम बंगाल में इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस इस चुनाव में 100 का आंकड़ा पार कर लेगी, किशोर ने कहा कि उन्हें लोकसभा में कांग्रेस की वर्तमान सीट की संख्या में बड़े बदलाव की संभावना नजर नहीं आती। **कांग्रेस के लिए चुनाव नतीजे में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं दिख रहा: प्रशांत किशोर** --उन्होंने कहा, अगर सीट की संख्या 50 - 55 हो जाए तो इससे देश की राजनीति नहीं बदल जाएगी। मुझे कांग्रेस के लिए चुनाव नतीजे में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं दिख रहा है। बड़े बदलाव के लिए कांग्रेस को 100 का आंकड़ा पार करना होगा। किशोर ने हालांकि कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार करेगी। उन्होंने कहा, आज की तारीख में यह बहुत मुश्किल है। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए 370 का यह लक्ष्य रखा है: प्रशांत किशोर भाजपा के 370 सीट जीतने के लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर किशोर ने कहा, भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए 370 का यह लक्ष्य रखा है। लोगों को इस 370 के लक्ष्य को सच नहीं मानना चाहिए। हर नेता को लक्ष्य तय करने का अधिकार है। यदि वे इसे हासिल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं कर पाते हैं तो पार्टी को इतना विनम्र होना चाहिए कि वह अपनी गलती स्वीकार कर ले। उनके मुताबिक, 2014 के बाद 8-9 चुनाव ऐसे हुए जहां भाजपा अपने तय लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। भाजपा अकेले 370 सीट हासिल नहीं कर सकती: प्रशांत किशोर किशोर ने कहा, मैं कह सकता हूं कि भाजपा अकेले 370 सीट हासिल नहीं कर सकती। इसकी संभावना करीब-करीब जीरो ही मानता हूं। अगर यह होता है तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। किशोर के अनुसार, अगर संदेशखालि जैसी घटना होती है, तो निश्चित रूप से वह सत्तारूढ़ दल के लिए नुकसान का कारण बनेगी। उनका मानना था कि भाजपा 2019 में पश्चिम बंगाल में मिली अपनी सीट से नीचे नहीं आएगी। पिछले चुनाव में भाजपा को पश्चिम बंगाल में 18 सीट हासिल हुई थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में किशोर ने कहा कि यह यात्रा का समय नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है।

जर्मनी में भांग को वैध किया गया, लेकिन सख्त नियमों के कारण खरीदना मुश्किल

इंटरनेशनल डेस्क- जर्मनी में भांग को वैध कर दिया गया है। कानून के तहत जर्मनी में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पर्याप्त मात्रा में भांग रखने की अनुमित मिल गई है लेकिन सख्त नियमों के तहत इसे खरीदना मुश्किल है। 1 अप्रैल से गांजा पीना वैध जर्मनी में 1 अप्रैल से कई सार्वजनिक स्थानों पर गांजा पीना वैध हो जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर दर्जनों मजबूत जोड़ों के बराबर 25 ग्राम तक का सामान रखने की अनुमति है। निजी घरों में कानूनी सीमा 50 ग्राम होगी। पहले से ही जर्मनी के कुछ हिस्सों, जैसे कि बर्लिन, में पुलिस अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर आंखें मूंद लेती है, हालांकि मनोरंजक उपयोग के लिए दवा रखना अवैध है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लॉटरबैक का कहना है कि मौजूदा कानून के बावजूद युवाओं के बीच दवा का उपयोग वर्षों से बढ़ रहा है। वह काले बाज़ार को कमज़ोर करना चाहता है। उन्होंने कहा कि धूम्रपान करने वालों को दूषित भांग से बचाना चाहता हैं और संगठित अपराध गिरोहों के लिए राजस्व धाराओं में कटौती करना चाहते हैं। लेकिन पूरे देश में वैध कैनबिस कैफे अचानक नहीं खुलेंगे। जर्मनी में कैनाबिस को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बारे में वर्षों से तीखी बहस चल रही है। डॉक्टरों ने जताई चिंता डॉक्टरों के समूहों ने युवा लोगों और रूढ़िवादियों के लिए चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे नशीली दवाओं के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। विपक्षी रूढ़िवादी सीडीयू के सिमोन बोरचर्ड ने जर्मनी की संसद बुंडेस्टाग को बताया कि सरकार डॉक्टरों, पुलिस और मनोचिकित्सकों की चेतावनियों की परवाह किए बिना अपने पूरी तरह से अनावश्यक, भ्रमित कानून के साथ आगे बढ़ी है। बाजार को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा लॉटरबैक ने कहा कि मौजूदा स्थिति अब तर्कसंगत नहीं है। पिछले 10 वर्षों में 18 से 25 वर्ष के बीच के उपभोक्ताओं की संख्या दोगुनी हो गई है। कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि स्कूलों और खेल के मैदानों के पास, भांग का धूम्रपान करना अभी भी अवैध होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा इसलिए दवा खरीदना आसान नहीं होगा। लाइसेंस प्राप्त दुकानों और फार्मेसियों को भांग बेचने की अनुमति देने की मूल योजना को यूरोपीय संघ की चिंताओं के कारण रद्द कर दिया गया है कि इससे दवा निर्यात में वृद्धि हो सकती है। तीन मारिजुआना पौधों की अनुमति होगी इसके बजाय, गैर-वाणिज्यिक सदस्यों के क्लब, जिन्हें कैनबिस सोशल क्लब कहा जाता है, सीमित मात्रा में दवा का विकास और वितरण करेंगे। प्रत्येक क्लब में 500 सदस्यों की ऊपरी सीमा होगी, साइट पर भांग का सेवन करने की अनुमति नहीं होगी और सदस्यता केवल जर्मन निवासियों के लिए उपलब्ध होगी। अपनी स्वयं की भांग उगाने की भी अनुमति होगी, प्रति घर अधिकतम तीन मारिजुआना पौधों की अनुमति होगी। काले बाज़ार को बढ़ावा मिलेगा इसका मतलब यह है कि जर्मनी बड़ी मात्रा में दवा रखने की अनुमति देने की विरोधाभासी स्थिति में हो सकता है, जबकि साथ ही इसे खरीदना मुश्किल हो सकता है। नियमित धूम्रपान करने वालों को लाभ होगा, लेकिन कभी-कभार धूम्रपान करने वालों को इसे कानूनी रूप से खरीदने में कठिनाई होगी और पर्यटकों को बाहर रखा जाएगा। आलोचकों का कहना है कि इससे सीधे तौर पर काले बाज़ार को बढ़ावा मिलेगा। सत्ता में आने पर कानून को खत्म कर देंगे- विपक्ष अगले कुछ वर्षों में, सरकार नए कानून के प्रभाव का आकलन करना चाहती है और अंततः भांग की लाइसेंस प्राप्त बिक्री शुरू करना चाहती है। लेकिन यह देखते हुए कि अब तक बहस कितनी जटिल रही है, कुछ भी निश्चित नहीं है। इस बीच विपक्षी रूढ़िवादियों का कहना है कि अगर वे अगले साल सरकार में आए तो इस कानून को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जर्मनी के जल्द ही यूरोप का नया एम्स्टर्डम बनने की संभावना नहीं है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569